Postal Regn. No. CG/RYP DN/108/2024-26

PRGI No. CHHHIN/2023/87466

लाईफ वर्सिटी

www.scgnews.in

वर्ष - 04 | अंक - 05 | अक्टूबर 2026 | मूल्य 50 रु



www.phzinfo.com

Positive Health Zone

Integrated Holistic
Health Care System

Unique Wellbeing Center



Holistic Healthcare Team

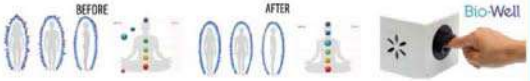
Our INTEGRATED SERVICES

Holistic Path Of Wellness & Wellbeing



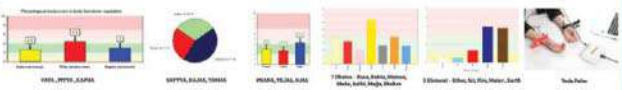
1. **Personal Energy Blueprint at Quantum Veda Lab with Latest Quantum Devices-**

   Aura, Chakra, Biofield, Lifeforce Energy Analysis.



2. **Digital Nadi Parikshan Modern Nadi Veda Pulse -**

   Personality Analysis
   Body Type, Mind Type, Energy Type.



3. **Life Style Clinic**

   Personalised Diet Plan, Lifestyle Plan, Day Plan, Detox Plan as per your Quantum Analysis.



4. **Body Detox & Rejuvenation with Kerala Ayurveda Panchkarma.**



5. **Mind Detox & Stress Management with NLP & Counselling.**



6. **Inner Alingment, Chakra Balancing with PNP Meditation.**



Get In Touch
9109185020, 9109185025

A-61, Amrapali Society,
Near Ganga Diagnostics, Raipur, Chhattisgarh

www.phzinfo.com

सम्पादक
नरेन्द्र कुमार पाण्डेय

प्रबंधक
हर्षित पाण्डेय

सलाहकार मण्डल
डॉ अनिल गुप्ता — रायपुर
प्रो. डॉ शुभ्रा सान्याल — नई दिल्ली

छत्तीसगढ़ कार्यालय
ए-32, आम्रपाली सोसाइटी, कलर्स मॉल के पीछे, पचपेड़ी नाका
रायपुर (छ.ग.)
मो. 88171-94979

मध्यप्रदेश कार्यालय
गोकुलधाम बेलौहान टोला,
सामान, रीवा मप्र

तेलंगाना कार्यालय
एफ-306, क्रिएटिव स्नेहा अपार्टमेंट, मस्जिद बंडा, बॉटनिकल गॉर्डन रोड, कोंडापुर, हैदराबाद-500084

प्रतिनिधि
अम्बुज अग्निहोत्री — जबलपुर
संजीव पाण्डेय — भोपाल
राजेश सिंह — बिलासपुर

कानूनी सलाहकार
संजयेंदु पंड्या

परिकल्पना
रजनीकांत पाण्डेय

समाचार स्रोत हमारे सभी संवाददाता/प्रतिनिधि। संदर्भ सामग्री: इंटरनेट, प्रमुख समाचार पत्र एवं नामचीन पत्रिकाओं से साभार। विवादग्रस्त न्यायिक प्रकरणों का कार्यक्षेत्र रायपुर न्यायालय रहेगा।

अंदर के पृष्ठों पर



03 शक्ति, सुरक्षा, आजादी और मर्यादा



8 चेहरे बदले....क्या बदलेगा छत्तीसगढ़ का राजनीतिक...



10 सेवा, सुशासन और जनकल्याण की बदलती तस्वीर



15 ज्योति से शक्ति तक

शेरनियों की दहाड़



17



22 स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं कागजों पर और मरीज जमीन में



26 उद्योगों से आगे विकास की उड़ान! बदलता बीरगांव

SCAN & PAY

UPI ID: 329044413263914@cnrb

लाईफ वर्सिटी के प्रचार–प्रसार में सहयोग करें।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - नरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा अंजलि प्रिंटर्स, हाउस नंबर 71/147, दवाड़ा कॉलोनी, पचपेड़ी नाका वार्ड 51, रायपुर छत्तीसगढ़ 492001 से मुद्रित एवं 6, विकास विहार कालोनी, सांई वाटिका,जोरातालाब के पास रायपुरा, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक- नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, मो. 88171-94979
E-mail : scgnewsraipur@gmail.com www.scgnews.in

शक्ति आराधना से सेवा-संकल्प तक



नरेन्द्र कुमार पाण्डेय
सम्पादक

शक्ति की आराधना का देश भारत। यहां दुर्गा की पूजा होती है, सरस्वती से ज्ञान और लक्ष्मी से समृद्धि की कामना की जाती है। लेकिन सवाल है–क्या हम शक्ति को केवल मंदिरों में पूजते हैं, या अपने समाज, व्यवस्था और व्यवहार में भी उसका सम्मान करते हैं?

जिस समाज में नारी को देवी कहा जाता है, वहां उसकी सुरक्षा और स्वतंत्रता आज भी चुनौती क्यों है? नारी-सशक्तीकरण केवल मंचों पर सम्मान देने तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसकी असली परीक्षा घर, कार्यस्थल और सामाजिक सोच में होती है। बेटी को अपनी आकांक्षाएं पूरी करने की स्वतंत्रता मिले, महिला की योग्यता को अवसर मिले और उसकी असहमति को भी समान महत्व मिले–तभी शक्ति की आराधना सार्थक होगी।

इसी तरह, आज का युवा केवल भविष्य के सपने नहीं देखता, वह वर्तमान से भी जवाब मांगता है। उसे शिक्षा, रोजगार और अवसर चाहिए, साथ ही निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी भी। क्या युवाओं को रोका जा सकता है? उनकी ऊर्जा को प्रतिबंधों से दबाने के बजाय संवाद, विश्वास और अवसरों से दिशा देना अधिक जरूरी है। युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों और विवेक के साथ अपनी बात रखें, वहीं सरकार और व्यवस्था का दायित्व है कि उनके सवालों को चुनौती नहीं, सुधार का अवसर समझें।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर हो रहे विरोध और मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर उठे सवाल भी लोकतंत्र की इसी कसौटी को सामने रखते हैं। विपक्ष ने कथित अनियमितताओं और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने पर आपत्तियां उठाई हैं, जबकि निर्वाचन सूची को अद्यतन करने के लिए अपात्र, मृत या दोहराए गए नामों को हटाना आवश्यक बताया जाता है। इन सवालों का समाधान आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि पारदर्शिता, प्रमाण और निष्पक्ष प्रक्रिया से होना चाहिए। विरोध का अधिकार लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन विरोध का तरीका भी जिम्मेदार होना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती इस बात में है कि नागरिक कितनी निर्भीकता से सवाल पूछ सकते हैं और उन्हें कितने निष्पक्ष जवाब मिलते हैं।

भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक भूमिका महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विकास की असली कसौटी आम नागरिक के जीवन में आया बदलाव है। रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और आर्थिक अवसर विकास को सार्थक बनाते हैं। इसी प्रकार, विदेश नीति की सफलता राष्ट्रीय हितों की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग के साथ देश की दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करने में है।

इन सभी विषयों को जोड़ने वाला सूत्र है–सेवा-संकल्प। शासन के लिए सेवा का अर्थ जवाबदेही, संस्थाओं के लिए निष्पक्षता, युवाओं के लिए समाजहित में अपनी प्रतिभा का उपयोग और नागरिकों के लिए अधिकारों के साथ कर्तव्यों का निर्वहन है।

आज आवश्यकता केवल शक्तिशाली भारत की कल्पना करने की नहीं, बल्कि ऐसा भारत बनाने की है जहां नारी निर्भय हो, युवा निराश न हो, नागरिक की आवाज अनसुनी न हो और विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। क्योंकि शक्ति का अर्थ केवल विजय नहीं, विश्वास है; केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है; केवल सत्ता नहीं, सेवा है।

आइए, स्वयं से पूछें–हम शक्ति की पूजा तो करते हैं, लेकिन क्या हम दूसरों को शक्तिशाली बनाने के लिए भी तैयार हैं?



शक्ति, सुरक्षा आजादी और मर्यादा

आज की सड़कों पर एक आवाज़ लगातार तेज हो रही है—'आज़ादी चाहिए-सुरक्षा चाहिए, बराबरी चाहिए।' महिलाएँ अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रही हैं। कहीं यह आवाज़ व्यवस्था से सवाल करती है, कहीं पितृसत्ता से, तो कहीं पुरुषों के प्रति इतना आक्रोश भी दिखाई देता है कि बहस एक नए सवाल पर आकर ठहर जाती है—क्या महिला मुक्ति की लड़ाई पुरुष-विरोध में बदल रही है? लेकिन शायद हमें नारों से थोड़ा आगे जाकर देखना चाहिए। क्योंकि हर आक्रोश के पीछे एक कहानी होती है। हर डर के पीछे कोई अनुभव होता है। और हर आज़ादी की मांग के पीछे किसी न किसी बंधन का अनुभव छिपा होता है।





एक लड़की रात में घर लौटते हुए सड़क को देखती है और अपने कदम तेज कर देती है। एक महिला workplace पर होने वाले व्यवहार को सहती है, क्योंकि उसे डर है कि आवाज उठाई तो उसकी नौकरी चली जाएगी। एक युवती सोशल mediaपर अपनी बात कहती है और कुछ ही मिनटों में उसे ट्रोलिंग और एब्यूज का सामना करना पड़ता है।

फिर सवाल उठता है—आखिर आज़ादी क्या है? क्या सिर्फ कानून हमें स्वतंत्र बना देता है? क्या सुरक्षा के बिना स्वतंत्रता पूरी हो सकती है? क्या महिला सशक्तिकरण के नारों से महिलाए सशक्त हो जाएँगी ? और क्या मर्यादा का अर्थ केवल महिलाओं के लिए बनाई गई सीमाएँ हैं?

यहीं से 'शक्ति' को समझने की हमारी यात्रा शुरू होती है। क्योंकि भारतीय परंपरा में शक्ति केवल देवी की पूजा का नाम नहीं रही। शक्ति सृजन भी है, संघर्ष भी है, संरक्षण भी है और परिवर्तन भी।

शक्ति केवल स्त्री का विषय नहीं है। शक्ति जीवन का विषय है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा हमें चलाती है, हमारे मन में जो हमें सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देती है, हमारे रिश्तों में जो हमें जोड़ती है और हमारी चेतना में जो जीवन को अर्थ देती है।

आज जब महिलाएँ सड़कों पर उतरती हैं, हाथों में तख्तियाँ होती हैं, आवाज़ में आक्रोश होता है और नारों में व्यवस्था से सवाल होते हैं, तब एक नया भारत हमारे सामने दिखाई देता है।

लेकिन इन आंदोलनों में कभी-कभी ऐसे नारे भी सुनाई देते हैं जो पूरे पुरुष वर्ग को कटघरे में खड़ा करते हैं।

सवाल यह नहीं कि वह नारा सही है या गलत। सवाल यह है कि आखिर वह आक्रोश पैदा क्यों हुआ? क्या यह केवल पुरुषों के खिलाफ गुस्सा है? या इसके पीछे वर्षों से जमा हुआ असुरक्षा का अनुभव है? जब कोई महिला कहती है—'हमें आज़ादी चाहिए।'

तो हमें पूछना चाहिए—आज़ादी किससे? घर के नियंत्रण से? सामाजिक दबाव से? हिंसा से? डिजिटल उत्पीड़न से? या उस डर से, जो उसे रात में अकेले सड़क पर निकलते समय घेर लेता है?और जब वह कहती है—'हमें सुरक्षा चाहिए।' तो सवाल और बड़ा हो जाता है—क्या किसी महिला को स्वतंत्र होने के लिए पहले सुरक्षित होना जरूरी है? शायद हाँ। लेकिन फिर एक दूसरा प्रश्न भी सामने आता है—आज़ादी और मर्यादा का रिश्ता क्या है? क्या मर्यादा का अर्थ सिर्फ महिलाओं के व्यवहार पर लगाए गए नियम हैं? या मर्यादा का एक अर्थ यह भी है कि हम अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल दूसरे की स्वतंत्रता और सम्मान को चोट पहुँचाए बिना करें? यहीं से हमारी कहानी वर्तमान आंदोलन से निकलकर अतीत की ओर जाती है।

बहुत पुरानी बात है। एक बार देवताओं को अपनी शक्ति पर इतना अभिमान हो गया कि उन्हें लगने लगा—हमसे अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है? तभी उनके सामने एक रहस्यमय यक्ष आया। अग्नि ने कहा—मैं सब कुछ जला सकता हूँ। वायु ने कहा—मैं सब कुछ उड़ा सकता हूँ। यक्ष ने उनके सामने एक छोटा-सा तिनका रख दिया।अग्नि उसे जला नहीं सका। वायु उसे हिला नहीं सका। देवताओं को पहली बार महसूस हुआ—जिसे वे अपनी शक्ति समझ रहे थे, उसके पीछे कोई और बड़ी शक्ति काम कर रही थी।

शक्ति क्या?

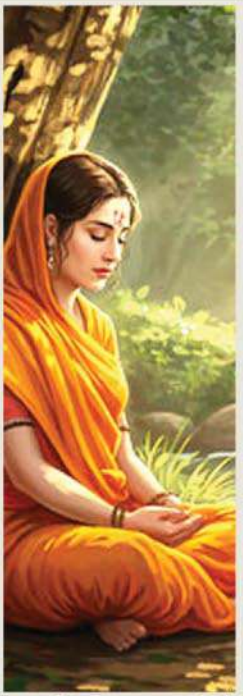
क्या शक्ति केवल वह है जो किसी को हराने की क्षमता देती है? क्या शक्ति केवल विरोध करने में है? क्या शक्ति केवल स्वतंत्र होने में है? या शक्ति वह ऊर्जा है जो सृजन करती है, संघर्ष करती है,संरक्षण करती है, परिवर्तन लाती है और अंततः चेतना को जागृत करती है? यहीं से शक्ति की हमारी यात्रा शुरू होती है।

आज की नारी : आक्रोश से आत्मनिर्णय तक

आज महिला आंदोलन केवल अधिकारों की मांग नहीं हैं। इनके भीतर आक्रोश, असुरक्षा, आत्मसम्मान और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की इच्छाभी दिखाई देती है। कई आंदोलनों में ऐसे नारे भी सुनाई देते हैं जो पुरुषों के प्रति अत्यंत आक्रामक या विरोधी हैं। इन्हें देखकर समाज दो हिस्सों में बंट जाता है—एक पक्ष कहता है कि महिलाएँ अपनी आवाज उठा रही हैं, दूसरा इसे पुरुष-विरोधी मानसिकता मानता है। आखिर वह आक्रोश पैदा क्यों हुआ?

हर महिला पुरुष-विरोधी नहीं है। लेकिन यदि किसी वर्ग की बड़ी संख्या लगातार सुरक्षा, सम्मान और समानता की बात कर रही है, तो समाज को केवल उसके नारों पर प्रतिक्रिया देने के बजायउस नाराजगी के कारणों को समझना चाहिए। नारी शक्ति का अर्थ पुरुष-विरोध नहीं, आत्मनिर्णय है। लेकिन आत्मनिर्णय के साथ एक और प्रश्न आता है—क्या स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी और मर्यादा भी जरूरी है?

गार्गी से Gen Z तक



गार्गी का सवाल था—सृष्टि के पीछे क्या है? आज की Gen Z लड़की पूछती है—मेरी जिंदगी का फैसला कौन करेगा? गार्गी ज्ञान की सभा में प्रश्न करती थीं। आज की लड़की classroom, workplace, social media और public space में अपनी आवाज उठा रही है। लेकिन आज की चुनौतियाँ भी नई हैं—Instagram comparison, body image, cyber bullying, trolling, relationship anxiety, career pressure और loneliness। इसलिए आज की महिला के सामने सवाल सिर्फ empowerment का नहीं है। Digital age में mental empowerment भी जरूरी है।

आज़ादीः अधिकार या जीवन जीने की बुनियादी जरूरत?

आज़ादी शब्द सुनते ही अक्सर राजनीतिक स्वतंत्रता याद आती है। लेकिन एक महिला के लिए आज़ादी के कई छोटे-छोटे अर्थ हो सकते हैं। वह तय कर सके—उसे क्या पढ़ना है। कौन सा करियर चुनना है। कब विवाह करना है। विवाह करना भी है या नहीं। कहाँ जाना है।अपनी कमाई कैसे खर्च करनी है। अपने शरीर और निजी जीवन के बारे में निर्णय कैसे लेना है।लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है—

कानून द्वारा मिली आज़ादी और वास्तविक जीवन में उपलब्ध आज़ादी एक जैसी नहीं होती। अगर लड़की के पास बाहर जाने की कानूनी स्वतंत्रता है, लेकिन उसे शाम के बाद अकेले निकलने में डर लगता है, तो क्या वह पूरी तरह स्वतंत्र है? अगर महिला नौकरी कर सकती है, लेकिन workplaceharassment के डर से आवाज नहीं उठा सकती, तो क्या वह वास्तव में स्वतंत्र है?

सुरक्षा : जब स्वतंत्रता डर के सामने रुक जाती है

महिला सुरक्षा को केवल अपराध के बाद की कार्रवाई के रूप में देखने के बजाय preventive social environment के रूप में देखना होगा। सड़क पर लाइटहै या नहीं? सीसीटीवी है या नहीं? पब्लिकट्रांसपोर्ट सुरक्षित है या नहीं? पुलिस की विजिबिलिटी है या नहीं? साइबरस्पेस में harassment की शिकायत पर कार्रवाई होती है या नहीं?

और इससे भी बड़ा सवाल—क्या लड़की को अपने आसपास के लोगों से डरना नहीं चाहिए? महिला सुरक्षा केवल महिलाओं का विषय नहीं है। यह परिवार, स्कूल, पुरुषों, प्रशासन, पुलिस, न्याय व्यवस्था और पूरे समाज का विषय है। और एक स्वस्थ समाज वह है जहाँ महिला अकेले भी सार्वजनिक स्थान पर स्वयं को सुरक्षित महसूस करे।

मर्यादाः नियंत्रण नहीं, आत्म-जिम्मेदारी

भारतीय समाज में 'मर्यादा' शब्द लंबे समय से इस्तेमाल होता रहा है लेकिन सवाल है—मर्यादा किसकी? क्या मर्यादा केवल महिला के पहनावे, व्यवहार और जीवनशैली के लिए है? अगर पुरुष महिला का सम्मान नहीं करता, तो क्या वह मर्यादा में है? अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी महिला को अपमानित करता है, तो क्या वह मर्यादा में है? अगर महिला अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करती है लेकिन दूसरे की गरिमा का सम्मान नहीं करती, तो क्या वह मर्यादा में है ? इसलिए मर्यादा को gender-specific बनाने के बजाय human value बनाना होगा। मर्यादा वह सीमा है जिसे हम दूसरे पर थोपते नहीं, बल्कि अपने आचरण में स्वयं स्वीकार करते हैं। और यह पुरुष और महिला दोनों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।

गार्गी का प्रश्न

प्राचीन भारतीय परंपरा की एक प्रसिद्ध कथा है—गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद। राजा जनक की सभा में विद्वानों का जमावड़ा था। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्म और अस्तित्व के बारे में प्रश्न किए। यहाँ कहानी का महत्व यह नहीं कि गार्गी ने कितने प्रश्न पूछे। महत्व यह है कि—एक महिला सार्वजनिक बौद्धिक संवाद में प्रश्न कर रही थी। नारी शक्ति का एक रूपप्रश्न करने का साहस भी है। मैत्रेयी का प्रसंग हमें एक अलग शक्ति दिखाता है। याज्ञवल्क्य के साथ उनके संवाद में संपत्ति और अमरत्व के प्रश्न के माध्यम से यह विचार सामने आता है कि भौतिक संपन्नता और वास्तविक आत्मज्ञान एक ही चीज नहीं हैं। मैत्रेयी इसलिए ज्ञान और आत्मबोध की खोज का प्रतीक बन सकती हैं।

लोपामुद्राका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और उनसे संबंधित सूक्त को वैदिक ऋषिका की परंपरा से जोड़ा जाता है। उनके प्रसंग मेंज्ञान, स्त्री की इच्छा, दांपत्य और आध्यात्मिक आकांक्षा—इन सबको साथ रखकर देखा जाय त्यों एक महत्वपूर्ण बात निकलती है कि वैदिक स्त्री को केवल त्याग और सहनशीलता की छवि में देखना अधूरा होगा।

तीनों अलग हैं, लेकिन इनके भीतर एक समान शक्ति दिखाई देती है—अपने अस्तित्व को स्वयं समझने और व्यक्त करने की शक्ति।शायद यही कारण है कि भारतीय परंपरा में नारी शक्ति को केवल बाहुबल या संघर्ष से नहीं समझा गया। वहप्रश्न में भी थी, ज्ञान में भी, सृजन में भी और आत्मबोध में भी। जिस स्त्री ने कभी ब्रह्मांड से प्रश्न किया था, आज उसकी आधुनिक उत्तराधिकारी अपने जीवन, अधिकार और समाज से प्रश्न कर रही है। फिर सवाल—बदल क्या? समय बदला है। संदर्भ बदले हैं। लेकिन प्रश्न करने की शक्ति शायद वही है। हजारों वर्ष बाद आज की Gen Z लड़की भी सवाल पूछ रही है—लेकिन उसके सवाल बदल गए हैं। गार्गी पूछती थीं—अस्तित्व के पीछे क्या है? मैत्रेयी पूछती थीं—क्या संपत्ति से अमरत्व मिल सकता है?और आज की युवती पूछ रही है—मेरी जिंदगी का फैसला मैं क्यों नहीं कर सकती? समय बदला है, सवालों का स्वरूप बदला है, लेकिन अपने जीवन पर अधिकार और अपने अस्तित्व को समझने की आकांक्षा—शायद वही है।



नवदुर्गा और दस महाविद्यायें

मानव चेतना के आयाम

- **शैलपुत्री** — स्थिरता अर्थात जीवन में जमीन से जुड़े रहने की क्षमता।
- **ब्रह्मचारिणी** — अनुशासन अर्थात लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास।
- **चंद्रघंटा** — सजगता अर्थात खतरे को पहचानना और प्रतिक्रिया देने की क्षमता।
- **कूष्मांडा** — सृजन अर्थात कुछ नया पैदा करने की ऊर्जा।
- **स्कंदमाता** — पोषण अर्थात दूसरों को विकसित करने की शक्ति।
- **कात्यायनी** — संघर्ष अर्थात अन्याय के सामने खड़े होने का साहस।
- **कालरात्रि** — भय का सामना अर्थात अपने डर से भागने के बजाय उसे देखने की क्षमता।
- **महागौरी** — संतुलन अर्थात शुद्धता और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक।
- **सिद्धिदात्री** — क्षमता अर्थात अपनी संभावनाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति।

इस तरह नवदुर्गा मंदिर से निकलकर हमारे व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाती हैं। फिर बात दशमहाविद्या की - शक्ति के वे रूप जिन्हें हम अपने भीतर स्वीकार नहीं करते , क्योंकि हम अपने भीतर केवल 'अच्छी' भावनाएँ देखना चाहते हैं। लेकिन मनुष्य के भीतर— क्रोध है। भय है। अकेलापन है। कामना है। अहंकार है। प्रतिस्पर्धा है। असुरक्षा है और दशमहाविद्या को प्रतीकात्मक रूप से मानव मन के जटिल आयामों को समझने का माध्यम बनाया जा सकता है।

- **काली** – परिवर्तन और अहंकार का विघटन।
- **तारा** – संकट में दिशा।
- **त्रिपुरसुंदरी** – सौंदर्य और संतुलन।
- **भुवनेश्वरी** – विस्तार।
- **भैरवी** – तप और साहस।
- **छिन्नमस्ता** – त्याग और ऊर्जा का रूपांतरण।
- **धूमावती** – अभाव और अकेलेपन का सामना।
- **बगलामुखी** – प्रतिक्रिया पर नियंत्रण।
- **मातंगी** – ज्ञान और अभिव्यक्ति।
- **कमला** – समृद्धि और पूर्णता।

अत: जिस शक्ति को हम स्वीकार नहीं करते, वही कई बार हमारे व्यवहार को भीतर से नियंत्रित करती है।





क्या हम महिलाओं को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, या केवल उनकी शक्ति को अपने हिसाब से नियंत्रित करना चाहते हैं? शक्ति किसी के विरुद्ध खड़े होने का नाम नहीं। शक्ति अपने भीतर इतना प्रकाश पैदा करना है कि भय कम हो, चेतना बढ़े और जीवन अपनी पूरी क्षमता से जिया जा सके।

शिव और शक्ति का प्रतीक हमें यह समझाता है कि—चेतना और ऊर्जा अलग-अलग होकर अधूरे हैं। ऊर्जा है लेकिन दिशा नहीं—तो विनाश भी हो सकता है। दिशा है लेकिन ऊर्जा नहीं—तो संभावना निष्क्रिय रह सकती है। इसलिए—शक्ति को चेतना चाहिए और चेतना को अभिव्यक्ति के लिए शक्ति। यही बात व्यक्तिगत जीवन पर लागू होती है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ पुरुष को कमजोर करना नहीं। पुरुष की शक्ति का अर्थ महिला पर नियंत्रण करना नहीं। वास्तविक शक्ति वह है जो स्वयं को सक्षम बनाती है और दूसरे की गरिमा को सुरक्षित रखती है।

हम नवरात्रि में शक्ति की पूजा तो करते हैं, लेकिन क्या हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं? क्या हमारी शिक्षा हमें शक्तिशाली बनाती है? क्या हमारा परिवार हमें शक्तिशाली बनाता है? क्या हमारा समाज महिलाओं को सुरक्षित बनाता है? क्या हमारी स्वतंत्रता जिम्मेदारी से जुड़ी है? क्या हमारी मर्यादा सबके लिए समान है? और सबसे बड़ा प्रश्न—क्या हम अपनी Life Force Energy को पहचानते हैं?

शक्तिः मानव शरीर के चार स्तर–

Body : शरीर की **vitality. Mind:** विचार, भावनाएँ और मानसिक क्षमता। **Social :** रिश्तों, संवाद और belonging की ऊर्जा। **Spiritual :** जीवन के अर्थ, उद्देश्य और आत्मबोध की दिशा। तात्पर्य यह है कि जब **BODY-MIND-RELATIONSHIP-CONSCIOUSNESS** का संतुलन बिगड़ता है तो व्यक्ति में stress, emotional exhaustion, isolation और जीवन से disconnect जैसी स्थितियाँ बढ़ सकती हैं। इसलिए स्वास्थ्य को केवल 'बीमारी नहीं है' तक सीमित नहीं किया जा सकता। समग्र स्वास्थ्य का प्रश्न है—क्या हमारे पास जीवन जीने की ऊर्जा भी है?

क्योंकि शक्ति किसी के विरुद्ध खड़े होने का नाम नहीं। शक्ति अपने भीतर इतनी चेतना पैदा करने का नाम है कि हम भय से मुक्त होकर जी सकें, अन्याय के सामने खड़े हो सकें, दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान कर सकें और अपनी ऊर्जा को सृजन की दिशा दे सकें इस पूरी यात्रा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है—

शक्ति आखिर है कहाँ?

क्या वह मंदिर में है? नवदुर्गा के नौ रूपों में? दशमहाविद्या के रहस्यमय प्रतीकों में? गार्गी के प्रश्न में? लक्ष्मीबाई की तलवार में? या आज सड़क पर अपने अधिकार के लिए आवाज उठाती उस लड़की में? शायद जवाब है—इन सबमें। लेकिन शक्ति केवल विरोध करने की क्षमता नहीं है। शक्ति केवल जीतने की क्षमता भी नहीं है।

शक्ति है—डर के बावजूद सही बात कहने का साहस। शक्ति है—अन्याय के सामने खड़े होने की क्षमता। शक्ति है—सृजन करने की ऊर्जा।शक्ति है—दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान। शक्ति है—अपनी सीमाओं को पहचानकर भी अपनी संभावनाओं को विस्तार देना। और जब हम शक्ति को मानव चेतना से जोड़कर देखते हैं, तो तस्वीर और बड़ी हो जाती है। शक्ति हमारे शरीर की ऊर्जा,शक्तिहमारे मन की ऊर्जा, शक्ति हमारे रिश्तों की ऊर्जाऔर शक्तिहमारे भीतर जीवन के अर्थ की तलाश में है ।

ये सब मिलकर हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करते हैं। इसलिए शायद असली सशक्तिकरण यह नहीं किकौन किस पर भारी पड़े। असली सशक्तिकरण यह है कि—स्त्री भय से मुक्त हो, पुरुष अहंकार से मुक्त हो, रिश्ते नियंत्रण से मुक्त हों और समाज हिंसा और असम्मान से मुक्त हो। क्योंकि जिस शक्ति को जागृत करने की जरूरत है, वह किसी एक लिंग की शक्ति नहीं है। वह मानव शक्ति है। और शायद नवरात्रि की देवी, गार्गी का प्रश्न, आज की लड़की की आज़ादी और हमारे भीतर की Life Force Energy—सब हमें एक ही बात याद दिलाते हैं—शक्ति बाहर खोजने की चीज नहीं है। उसे पहचानना, संतुलित करना और सही दिशा देना ही असली शक्ति है। क्योंकि जब चेतना जागती है, तभी शक्ति सार्थक होती है।



चेहरे बदले क्या बदलेगा छत्तीसगढ़ का राजनीतिक मिजाज?



भाजपा में प्रभारी और संगठन महामंत्री बदले, कांग्रेस में भी नई कमान; सामने निकाय चुनाव की पहली परीक्षा, 2028 से पहले दोनों दलों के सामने कार्यकर्ता और संगठन को साथ रखने की चुनौती

लाईफ वर्सिटी

छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा बदलाव भाषणों में नहीं, संगठन के भीतर हो रहा है। कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी बदला है तो भाजपा ने भी प्रदेश प्रभारी के साथ संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी बदल दी है।

ऊपर से देखने पर यह सामान्य संगठनात्मक फेरबदल दिखाई दे सकता है, लेकिन राजनीति को करीब से देखने वालों के लिए यह 2028 की लड़ाई की शुरुआती तैयारी का संकेत है।

भाजपा ने स्मृति ईरानी को प्रदेश प्रभारी, सिद्धार्थ शंभू को सह-प्रभारी और कर्मवीर सिंह को प्रदेश महामंत्री (संगठन)बनाया है। पवन साय को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है।

दूसरी ओर कांग्रेस में सुखदेव भगत को नया प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। अपने शुरुआती दौर में ही भगत ने संगठन की समीक्षा और जिम्मेदारी नहीं निभाने वाले पदाधिकारियों को बदलने की बात कही है। यानी कांग्रेस के भीतर भी साफ संदेश है कि केवल पदाधिकारी बदलने से काम नहीं चलेगा, संगठन को सक्रिय करना होगा। लेकिन यह है—क्या नए चेहरे उस राजनीतिक बेचैनी को बदल पाएंगे जो दोनों दलों के भीतर दिखाई दे रही है?

भाजपा के सामने सत्ता की सुविधा और संगठन की बेचैनी

भाजपा के पास सबसे बड़ा लाभ सत्ता का है। सरकार को अभी विधानसभा चुनाव के लिए पर्याप्त समय मिला हुआ है। संगठन भी बूथ स्तर तक फैला हुआ है। लेकिन सत्ता में रहने का अपना खतरा भी होता है।

पार्टी के भीतर से निकल रही चर्चाओं में कार्यकर्ताओं की नाराजगी, स्थानीय स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी तथाअफसरशाही के बढ़ते प्रभावकी शिकायतें सुनाई देती हैं। इन चर्चाओं को किसी एक व्यक्ति या क्षेत्र की समस्या मानना ठीक नहीं होगा, लेकिन यदि ऐसी भावना कई इलाकों में बन रही है तो चुनावी राजनीति में इसका असर पड़ सकता है।

भाजपा का सबसे बड़ा चुनावी बल उसका कार्यकर्ता है। यदि वही कार्यकर्ता यह महसूस करने लगे कि सरकार में उसकी सुनवाई कम है और निर्णय प्रक्रिया में अधिकारियों की भूमिका ज्यादा है, तो इसका असर चुनाव के समय दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि कर्मवीर सिंह की नियुक्ति सिर्फ संगठन महामंत्री बदलने की घटना नहीं है।उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण काम संगठन और सरकार के बीच संवाद को मजबूत करना होगा।

स्मृति ईरानी के सामने दूसरी चुनौती होगी—राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों को समझकर संगठन को चुनावी दिशा देना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनकी नियुक्ति का स्वागत करते हुए कहा है कि उनके अनुभव से संगठन मजबूत होगा।लेकिन भाजपा के लिए सवाल यही है किक्या दिल्ली से आया मजबूत चेहरा छत्तीसगढ़ के स्थानीय असंतोष को समझ पाएगा?

निकाय चुनाव भाजपा के लिए पहली अग्निपरीक्षा

यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब दिसंबर 2026 में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनावों की तैयारी तेज हो रही है। राज्य के चार बड़े नगर निगम—भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरौदा और बीरगांव—सहित कई नगरीय निकायों में चुनाव प्रस्तावित हैं।यही चुनाव नए भाजपा संगठन की पहली वास्तविक परीक्षा बन सकते हैं।

विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय नेतृत्व, मोदी सरकार और सत्ता का प्रभाव अलग तरह से काम करता है। लेकिन निकाय चुनाव में मुकाबला बहुत स्थानीय होता है। यहां उम्मीदवार का व्यक्तिगत संपर्क, वार्ड की सड़क, पानी, सफाई, रोजगार, स्थानीय नेता की पकड़ और कार्यकर्ताओं की सक्रियता ज्यादा मायने रखती है।

इसलिए यदि भाजपा कार्यकर्ताओं की



नाराजगी केवल राजनीतिक गलियारों की चर्चा है तो वह चुनाव में दिखाई नहीं देगी। लेकिन यदि यह असंतोष वास्तव में बूथ स्तर तक पहुंच चुका है, तो निकाय चुनाव उसका पहला संकेत दे सकते हैं।

भाजपा के लिए यह चुनाव जीतने से ज्यादा संगठन की सेहत जांचने का चुनाव होगा। कांग्रेस की समस्या सत्ता विरोधी माहौल से ज्यादा 'साथ चलने' की है

कांग्रेस की चुनौती भाजपा से अलग है



कांग्रेस विपक्ष में है, इसलिए उसे सरकार के खिलाफ स्वाभाविक राजनीतिक जमीन मिल सकती है। स्वास्थ्य, बेरोजगारी, किसानों, स्थानीय विकास और प्रशासनिक कार्यप्रणाली जैसे मुद्दे उसके पास हैं।लेकिन इन मुद्दों को चुनावी ताकत में बदलने के लिए कांग्रेस को पहलेअपने भीतर एकता पैदा करनी होगी।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी लंबे समय से यही रही है कि उसके पास कई प्रभावशाली नेता हैं, लेकिन उन्हें एक राजनीतिक दिशा में साथ चलाना आसान नहीं रहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अपना प्रभाव है, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का अपना राजनीतिक आधार है, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की अपनी संगठनात्मक भूमिका है , पूर्व डिप्टी सीएम टी एस सिंह देव की अपनी महत्ता और अलग-अलग



क्षेत्रों में दूसरे वरिष्ठ नेताओं के अपने समर्थक हैं।

नए प्रभारी सुखदेव भगत के सामने इसलिए सबसे कठिन काम किसी एक गुट को मजबूत करना नहीं, बल्कि सभी गुटों को एक चुनावी मंच पर खड़ा करना होगा।हाल में कांग्रेस ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर प्रदेशभर में प्रदर्शन किया, जिसमें भगत, दीपक बैज, चरणदास महंत और भूपेश बघेल सहित कई नेता साथ दिखाई दिए।यह तस्वीर महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनावी एकता का असली परीक्षण तब होगा जब टिकट बंटेंगे और स्थानीय स्तर पर दावेदार आमने-सामने होंगे।

निकाय चुनाव बताएंगे किसका कार्यकर्ता किसके साथ है

निकाय चुनावों में दोनों पार्टियों की असली परीक्षा यहीं होगी। भाजपा को देखना होगा किसरकार की लोकप्रियता और संगठन की मशीनरी के बीच कोई दूरी तो नहीं बन रही। कांग्रेस को देखना होगा कि वह अपनी गुटीय राजनीति से ऊपर उठकर उम्मीदवार के पीछे पूरी ताकत से खड़ी हो सकती है या नहीं। क्योंकि निकाय चुनाव में बड़े नेता प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वोट बूथ का कार्यकर्ता ही जुटाता है।

2028 की लड़ाई अभी से शुरु

अगर निकाय चुनाव में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो पार्टी के भीतर यह संदेश जाएगा कि सरकार के खिलाफ संभावित असंतोष अभी चुनावी स्तर तक नहीं पहुंचा है। इससे 2028 के लिए भाजपा का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके उलट यदि भाजपा को अपने मजबूत माने जाने वाले शहरी क्षेत्रों में झटका लगता है, तो पार्टी नेतृत्व को यह संकेत मिलेगा किसत्ता और संगठन के बीच कहीं न कहीं दूरी पैदा हो रही है।

कौन-सा दल अपने कार्यकर्ता को यह भरोसा दिला पाता है कि उसकी मेहनत की कीमत है, उसकी बात सुनी जाती है और नेतृत्व चुनाव के समय ही नहीं, पूरे पांच साल उसके साथ खड़ा है—छत्तीसगढ़ की अगली राजनीतिक कहानी काफी हद तक इसी सवाल से तय होगी।

कांग्रेस के लिए भी यही समीकरण उलटा है। अगर वह गुटबाजी के बावजूद निकाय चुनाव में मजबूत प्रदर्शन करती है तो यह 2028 के लिए विपक्ष कीवापसी की जमीन तैयार कर सकता है। लेकिन यदि स्थानीय स्तर पर टिकट और नेतृत्व को लेकर खींचतान हावी रही तो सरकार विरोधी माहौल का लाभ भी कांग्रेस के हाथ से निकल सकता है।

लड़ाई चेहरे की नहीं, भरोसे की है

छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस समय सबसे दिलचस्प स्थिति यही है किदोनों दल अपने-अपने स्तर पर संगठन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों की समस्याएं अलग-अलग रूप में एक जैसी हैं।भाजपा के सामने सत्ता से पैदा हुई दूरी और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं का सवाल है। कांग्रेस के सामने गुटों से ऊपर उठकर साथ चलने की चुनौती है।

भाजपा के नए प्रभारी और संगठन महामंत्री को यह साबित करना होगा कि संगठन सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होने वाली मशीन नहीं है। कांग्रेस के नए प्रभारी को यह साबित करना होगा कि अलग-अलग नेताओं की ताकत को एक साझा चुनावी ताकत में बदला जा सकता है।और यही कारण है कि आने वाले निकाय चुनावों को केवल नगर सरकार बनाने का चुनाव समझना भूल होगी। यह दोनों दलों के लिए2028 का पूर्वाभ्यास होंगे। कौन-सा दल अपने कार्यकर्ता को यह भरोसा दिला पाता है कि उसकी मेहनत की कीमत है, उसकी बात सुनी जाती है और नेतृत्व चुनाव के समय ही नहीं, पूरे पांच साल उसके साथ खड़ा है—छत्तीसगढ़ की अगली राजनीतिक कहानी काफी हद तक इसी सवाल से तय होगी। राजनीतिक चेहरों का बदलाव हो चुका है। अब देखना यह है कि क्या राजनीतिक संस्कृति भी बदलती है।

विष्णुभैया की विकास दृष्टि

सेवा, सुशासन और जनकल्याण की बदलती तस्वीर



मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विकास दृष्टि का केंद्र योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाना, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना और जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना है। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, मातृत्व सहायता, आवास, दिव्यांगजनों की सुविधा और ग्रामीण विद्युतीकरण से जुड़ी पहलें इसी व्यापक उद्देश्य के अलग-अलग आयाम प्रस्तुत करती हैं।

लाईफ वर्सिटी

विकास की असली पहचान केवल बड़ी परियोजनाओं, बजट और सरकारी घोषणाओं में नहीं, बल्कि आम आदमी के जीवन में आने वाले बदलावों में होती है। जब किसी दूरस्थ गाँव के बच्चे को बेहतर शिक्षा मिलती है, महिला आत्मनिर्भर बनती है, जरूरतमंद परिवार को पक्का घर मिलता है और दिव्यांग विद्यार्थी के लिए आगे बढ़ने की राह आसान होती है, तभी विकास का अर्थ सार्थक होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवा गतिविधियों को आम नागरिक की जरूरतों से जोड़ने का प्रयास इसी सोच को सामने लाता है। सेवा संकल्प अभियान इस दिशा में शासन और समाज की भागीदारी को एक साथ आगे बढ़ाने की पहल है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विकास दृष्टि का केंद्र योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाना, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना और जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना है। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, मातृत्व सहायता, आवास, दिव्यांगजनों की सुविधा और ग्रामीण विद्युतीकरण से जुड़ी पहलें इसी व्यापक उद्देश्य के अलग-अलग आयाम प्रस्तुत करती हैं।

बस्तर में शिक्षा के नए अवसर, भविष्य की नई उम्मीद



जनजातीय अंचलों में विकास का अर्थ केवल आधारभूत ढाँचे का विस्तार नहीं, बल्कि बच्चों के लिए शिक्षा और बेहतर भविष्य के अवसर तैयार करना भी है। नारायणपुर जिले के भाटपाल में कभी सुरक्षा शिविर के रूप में उपयोग होने वाला परिसर अब विद्यार्थियों के लिए छात्रावास के रूप में उपयोग किया जा रहा है। यह बदलाव शिक्षा के विस्तार और स्थानीय बच्चों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण उदाहरण है।

राजबेड़ा के कोमेंद्र कक्षा 12वीं में और हलामीमुंजमेटा के रितेश सोनी कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हैं। यहाँ प्री-मैट्रिक छात्रावास में कक्षा 6वीं से 10वीं तक के 114 और पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के 39 विद्यार्थी रह रहे हैं।

इन आँकड़ों के पीछे उन परिवारों की

उम्मीदें हैं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास की सार्थकता ऐसे अवसरों के विस्तार से भी आँकी जा सकती है, जो दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को अपने सपने पूरे करने का आधार देते हैं।

महिला सशक्तिकरण : हुनर से आत्मनिर्भरता तक



महिला सशक्तिकरण तब वास्तविक रूप लेता है, जब महिलाओं को अपनी आजीविका चलाने, आर्थिक निर्णय लेने और परिवार की प्रगति में भागीदारी का अवसर मिलता है। सरगुजा जिले के लटौरी में 20 महिलाएँ खस से हस्तशिल्प उत्पाद तैयार कर रही हैं। स्थानीय हुनर को रोजगार से जोड़ने वाला यह प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला समूहों की भूमिका को रेखांकित करता है।

मेंद्रा खुर्द की पुष्पा राजवाड़े ने बिहान स्व-सहायता समूह से जुड़कर टेंट व्यवसाय शुरू किया। ऋण की सहायता से उन्होंने आगे चलकर ट्रैक्टर खरीदा और अब खेती के साथ ट्रैक्टर किराये पर देने से भी आय अर्जित कर रही हैं। इसी तरह बतौली क्षेत्र के तरागी गाँव की सूरजपति ने स्व-सहायता समूह से 60 हजार रुपये का ऋण लेकर ऑटो और किराना व्यवसाय शुरू किया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इससे उन्हें प्रतिदिन लगभग 500 रुपये की आय हो रही है।

ये कहानियाँ बताती हैं कि वित्तीय सहायता, स्थानीय अवसर और महिलाओं की मेहनत मिलकर परिवार की आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं। ऐसी पहलें आत्मनिर्भरता को केवल नारे के बजाय आजीविका और आत्मविश्वास से जोड़ती हैं।

मातृत्व को संबल, परिवार को सहारा



जनकल्याण का एक महत्वपूर्ण आयाम महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण तथा आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है। पेंड्रा क्षेत्र के अमादांड की वर्षा पुरी को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत सहायता मिली, जिससे नवजात शिशु की देखभाल में सहयोग मिला। वहीं, धरमजयगढ़ क्षेत्र के बिरसिंघा गाँव की बिरहोर समुदाय से आने वाली कमला बाई महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली एक हजार रुपये की मासिक सहायता का उपयोग घरेलू जरूरतों और किराना सामग्री के लिए करती हैं।

आँगन मिलन जैसे आयोजनों में गोद भराई, अन्नप्राशन, पोषण जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन गतिविधियों का उद्देश्य आर्थिक सहायता के साथ माँ और बच्चे के स्वास्थ्य तथा पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है।

पक्के घर से सुरक्षा और सम्मान



अपना घर हर परिवार के लिए सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान का प्रतीक है। जशपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,12,948 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 96,801 पूरे हो चुके हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों के लिए पीएम-जनमन के तहत आवास की पहल भी महत्वपूर्ण है। पक्की छत केवल मौसम से बचाव नहीं करती, बल्कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण और परिवार को स्थिरता देती है। जनकल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक प्रभाव तब सामने आता है, जब वे लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करके बेहतर जीवन की संभावनाएँ बढ़ाती हैं।

सुविधा से स्वतंत्रता तक - दिव्यांग विद्यार्थी को सहारा



रायगढ़ जिले के उसरौट के दिव्यांग विद्यार्थी हिमेश कुमार पटेल को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई गई। उनके लिए यह केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा जारी रखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहयोग है।

समावेशी विकास का अर्थ है कि शारीरिक चुनौतियों या परिस्थितियों के कारण किसी व्यक्ति के अवसर सीमित न हों। ऐसी सुविधाएँ दिव्यांगजनों की स्वतंत्रता बढ़ाने और उन्हें शिक्षा तथा सामाजिक जीवन में अधिक भागीदारी का अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

दूरस्थ गाँवों तक रोशनी, अवसरों का विस्तार



ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता शिक्षा, आजीविका और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी है। गावलगुंडी में विद्युतीकरण तथा नटहवाही के चेरवापारा में सौर ऊर्जा व्यवस्था से 54 घरों को लाभ मिलने की जानकारी है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, 101 सौर संयंत्रों की कुल क्षमता 496 किलोवाट है और इनसे 2,993 घरों को लाभ मिला है।

दूरस्थ बस्तियों तक ऊर्जा पहुँचने से बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कामकाज और छोटे व्यवसायों के लिए अवसर बढ़ते हैं। यह विकास की उस दिशा को दर्शाता है, जिसमें भौगोलिक दूरी के कारण कोई क्षेत्र सुविधाओं से वंचित न रहे।

सेवा संकल्प: शासन के साथ समाज की भागीदारी



मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सेवा संकल्प अभियान जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचाने और सामाजिक सहभागिता बढ़ाने का माध्यम है। स्वच्छता, पौधरोपण, रक्तदान, सेवा ज्योति यात्रा और सेवा सेतु जैसी गतिविधियाँ नागरिकों को सेवा के कार्यों से जोड़ती हैं। जशपुर के तपकरा स्थित शासकीय महाविद्यालय में रक्तदान शिविर जैसी पहलें भी समाज के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश देती हैं।

विकास केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है। जब प्रशासन, सामाजिक संस्थाएँ, युवा और आम नागरिक एक उद्देश्य से जुड़ते हैं, तब जनकल्याण के प्रयासों का दायरा बढ़ता है। यही जनभागीदारी सेवा संकल्प की भावना को व्यापक बनाती है।

> “विकास केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है। जब प्रशासन, सामाजिक संस्थाएँ, युवा और आम नागरिक एक उद्देश्य से जुड़ते हैं, तब जनकल्याण के प्रयासों का दायरा बढ़ता है। यही जनभागीदारी सेवा संकल्प की भावना को व्यापक बनाती है।”

नेतृत्व की कसौटी: लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे



मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की इन पहलों में एक साझा उद्देश्य दिखाई देता है—सरकारी योजनाओं को आम नागरिक की जरूरतों से जोड़ना। शिक्षा प्राप्त करते बच्चे, स्वरोजगार से आगे बढ़ती महिलाएँ, मातृत्व सहायता से लाभान्वित परिवार, आवास की सुविधा पाने वाले हितग्राही और आवागमन में सहारा पाने वाले दिव्यांग विद्यार्थी विकास के इसी मानवीय पक्ष को सामने लाते हैं। हालाँकि, किसी भी योजना की स्थायी सफलता इस बात से तय होती है कि उसका लाभ पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुँचे, प्रक्रिया सरल हो, सुविधाएँ लंबे समय तक उपयोगी बनी रहें और लोगों की समस्याओं का समाधान लगातार होता रहे।

विष्णु भैया के नेतृत्व में संवरते छत्तीसगढ़ की तस्वीर इन कहानियों में दिखाई देती है। विकास का असली अर्थ तभी पूरा होता है, जब शासन की पहल लोगों के जीवन में अवसर, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान बढ़ाए। सेवा संकल्प की सार्थकता भी इसी में है—योजनाएँ जन-जन तक पहुँचें, समाज सहभागी बने और विकास का लाभ छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र तथा हर वर्ग तक पहुँचे।

सिंगापुर से छत्तीसगढ़ तक विकास की नई संभावनाएँ



निवेश, कौशल और रोजगार पर नजर

एक ओर खनिज संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़, दूसरी ओर आधुनिक तकनीक और वैश्विक व्यापार के लिए पहचाना जाने वाला सिंगापुर। इन दोनों के बीच साझेदारी का नया रास्ता तलाशने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सिंगापुर दौरा महत्वपूर्ण रहा। लेकिन इस यात्रा की असली सफलता केवल निवेश के बड़े आंकड़ों में नहीं, बल्कि इस बात में होगी कि इनसे छत्तीसगढ़ के युवाओं, किसानों और स्थानीय उद्यमियों को कितना लाभ मिलता है।

3 से 6 अक्टूबर 2026 तक चले इस दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ को लगभग 43,600 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश प्रस्ताव और प्रतिबद्धताएँ मिलीं। मुख्यमंत्री ने Singapore-India Network for Growth (SING) Forum 2026 में राज्य की औद्योगिक संभावनाएँ प्रस्तुत कीं और वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से निवेश एवं सहयोग पर चर्चा की।

निवेश के नए अवसर

दौरे की प्रमुख घोषणाओं में सिंगापुर की Energy Capital Global की ओर से लगभग41,750 करोड़ रुपये के AI-सक्षम डेटा सेंटर परिसरकी प्रतिबद्धता शामिल है। इसके अतिरिक्त, 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना और बैटरी भंडारण के लिए 1,500 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता सामने आई। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में Valency International ने लगभग 350 करोड़ रुपये के एकीकृत प्रसंस्करण और निर्यात केंद्र का प्रस्ताव दिया।

ये पहल छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को पारंपरिक खनिज और विनिर्माण क्षेत्रों से आगे बढ़ाने की संभावना रखती हैं। डेटा सेंटर डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं, जबकि कृषि प्रसंस्करण केंद्र किसानों की उपज को मूल्यवर्धित उत्पादों और बड़े बाजारों से जोड़ने में मदद कर सकता है।

युवाओं के कौशल पर जोर

दौरे की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिंगापुर की ITE Education Services के साथ तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए समझौताहै। इसका उद्देश्य उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप युवाओं का कौशल विकसित करना है।

आज उद्योगों को केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण और तकनीकी दक्षता वाले युवाओं की जरूरत है। यदि इस सहयोग से छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक पाठ्यक्रम और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण विकसित होते हैं, तो प्रदेश के युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर अवसर मिल सकते हैं।

असली कसौटी होगी क्रियान्वयन

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सिंगापुर दौरा राज्य को वैश्विक निवेश, तकनीकी शिक्षा और नए व्यावसायिक सहयोग से जोड़ने की पहल है। अब अगला चरण इन प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने का है। कितने रोजगार बनते हैं, स्थानीय युवाओं को कितना प्रशिक्षण मिलता है, किसानों को नए बाजारों से कितना लाभ मिलता है और स्थानीय उद्यमियों की भागीदारी कितनी बढ़ती है—इन सवालों के जवाब ही इस पहल के वास्तविक प्रभाव को स्पष्ट करेंगे।

छत्तीसगढ़ की प्रगति का पैमाना केवल निवेश की राशि नहीं, बल्कि उससे पैदा होने वाले अवसर होंगे।सिंगापुर में बनी साझेदारियों को यदि प्रदेश के गाँवों, खेतों, उद्योगों और युवाओं तक पहुँचाया जा सका, तो यह दौरा राज्य की विकास यात्रा में सार्थक भूमिका निभा सकता है।



ज्योति से शक्ति तक

नवरात्रि की अखंड ज्योति और कुमारी पूजन का अनकहा रहस्य

शक्ति हमेशा विराट रूप में दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं। कभी वह दुर्गा बनकर सामने आती है। कभी महाकाली बनकर। और कभी एक मासूम कन्या के रूप में। इसलिए किसी को उसके बाहरी रूप, उम्र या शारीरिक सामर्थ्य से कमजोर समझ लेना भूल हो सकती है।

नवरात्रि आते ही हमारे घरों और मंदिरों में एक दीपक प्रज्वलित होता है—ज्योति कलश, अखंड ज्योति। नौ दिनों तक जलती यह ज्योति हमारे लिए पूजा का हिस्सा है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि नवरात्रि में ज्योति ही क्यों जलाई जाती है?

क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे देवी के प्राकट्य से जुड़ा कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? और इससे भी बड़ा प्रश्न—जिस देवी का प्राकट्य स्वयं देवताओं के तेज और उनके सामूहिक समर्पण से हुआ, क्या उनकी कथा आज के मनुष्य को सेवा, सहयोग और अंगदान जैसे मानवीय मूल्यों का संदेश भी देती है?

शायद नवरात्रि की ज्योति को समझने के लिए हमें उस क्षण तक लौटना होगा, जब आदिशक्ति पहली बार तेजोमय शक्ति के रूप में प्रकट हुई थीं। देवीमाहात्म्य अर्थात् दुर्गा सप्तशती की कथा के अनुसार महिषासुर ने इन्द्र सहित देवताओं को पराजित कर दिया था। देवता अपनी सत्ता और स्वतंत्रता खो चुके थे। उसके अत्याचार से त्रस्त होकर वे ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे।

देवताओं की पीड़ा और महिषासुर के अत्याचार से भगवान विष्णु, भगवान शिव तथा अन्य देवताओं के भीतर प्रचंड तेज उत्पन्न हुआ। अलग-अलग दिशाओं से निकला यह तेज एक स्थान पर एकत्र होने लगा और देखते ही देखते एक अद्भुत, प्रचंड ज्योति-पुंज के रूप में प्रकट हुआ।

यही तेज आगे चलकर महामाया भगवती के रूप में प्रकट हुआ। अर्थात देवी का पहला प्राकट्य केवल किसी मूर्ति या स्त्री-स्वरूप में नहीं, बल्कि ज्योति और तेज के रूप में हुआ। यहीं से नवरात्रि की अखंड ज्योति को समझने की पहली कड़ी जुड़ती है।

देवी किसी एक देवता की शक्ति से नहीं बनीं। विभिन्न देवताओं ने अपने-अपने तेज का अंश समर्पित किया। पुराणों में वर्णन मिलता है कि- शिव के तेज से मुख, विष्णु के तेज से भुजाएं, यम के तेज से केश, चंद्रमा के तेज से वक्ष, इन्द्र के तेज से कटिप्रदेश और अन्य देवताओं के तेज से देवी के विभिन्न अंगों की उत्पत्ति बताई गई है। इसके बाद देवताओं ने अपने अस्त्र-शस्त्र भी देवी को अर्पित किए।

संदेश स्पष्ट है—शक्ति किसी एक के पास नहीं थी। शक्ति सबके पास थी। लेकिन जब



शहीद नगर, भिलाई (दुर्ग) स्थित
श्री महाकाली दरबार, दस महाविद्या मंदिर

सबने अपनी शक्ति का अंश समर्पित किया, तब वह शक्ति विराट बन गई।

आज इसी विचार को हम अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। और अंगदान इसका एक आधुनिक उदाहरण है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके उपयोगी अंग किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन दे सकते हैं। आंखें किसी को दुनिया देखने का अवसर दे सकती हैं। इसी तरह लीवर,किडनी,हार्ट जैसे अंग किसी दूसरे परिवार में उम्मीद बन सकता है।

देवताओं ने अपना तेज दिया और देवी का विराट स्वरूप प्रकट हुआ। उसी तरह मनुष्य भी अपने जीवन में उपलब्ध रक्त, समय, ज्ञान, श्रम और संसाधनों का कुछ हिस्सा समाज को देकर किसी दूसरे के जीवन में प्रकाश बन सकता है।

रक्तदान किसी की जान बचा सकता है। ज्ञानदान किसी का भविष्य बदल सकता है। समयदान किसी अकेले व्यक्ति को सहारा दे सकता है। श्रमदान किसी समुदाय की तस्वीर बदल सकता है। और मृत्यु के बाद अंगदान किसी को जीवन की नई संभावना दे सकता है। इसलिए समर्पण का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है। यह मनुष्य की शक्ति को समाज की शक्ति में बदलने का माध्यम है।

ज्योति क्यों ?

अब वापस उस ज्योति की ओर लौटिए। दीपक की लौ को ध्यान से देखिए। उसकी स्वाभाविक दिशा ऊपर की ओर होती है। यही लौ हमें जीवन का संदेश देती है—परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमारी दिशा ऊपर की ओर होनी चाहिए।

अज्ञान से ज्ञान की ओर।
निराशा से आशा की ओर।
स्वार्थ से सेवा की ओर।
अलगाव से सहयोग की ओर।
और केवल 'मैं' से 'हम' की ओर।

इसलिए ज्योति कलश केवल पूजा का पात्र नहीं है। यह मनुष्य के भीतर प्रकाश, ऊर्जा और समर्पण जगाने का प्रतीक है। नवरात्रि के नौ दिनों तक हम बाहर अखंड ज्योति जलाते हैं। लेकिन असली प्रश्न यह है—क्या हमारे भीतर भी ज्योति अखंड है?

क्या हमारे भीतर ज्ञान की ज्योति जल रही है? क्या हमारे कर्म में ऊर्जा है? क्या हमारी इंद्रियों में संयम है? क्या हमारे भीतर सेवा की भावना जीवित है? बाहर का दीपक नौ दिनों तक प्रकाश देगा, लेकिन भीतर की ज्योति यदि जाग जाए तो वह पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है।

यहाँ एक बात और महत्व पूर्ण है - नवरात्रि में नौ दिनों तक ज्योति प्रज्वलित करने का संबंध देवी के नौ स्वरूपों अर्थात् नवदुर्गा की उपासना से है। और परंपरागत अंक-चिंतन में भी नौ को विशेष महत्व दिया गया है। आधुनिक विज्ञान के निकोलस टेस्ला ने भी 3-6-9 अंको को ब्रह्मांडीय ऊर्जा बतलाया है ।

एक दिन-रात में 24 घंटे होते हैं। 9 दिनों तक ज्योति जलती है -

24 × 9 = 216

और 216 के अंकों को जोड़ने पर—

2 + 1 + 6 = 9

अर्थात अंतिम अंक फिर नौ ही आता है। इसे नवरात्रि के नौ दिनों और नवशक्ति के साथ जोड़कर एक प्रतीकात्मक व्याख्या के रूप में देखा जा सकता है।

देवी कुमारी क्यों है ?

नवरात्रि की ज्योति के बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है—कुमारी पूजन क्यों? हम माँ दुर्गा और माँ काली की पूजा करते हैं, लेकिन नवरात्रि में एक छोटी-सी कन्या को घर बुलाकर उसके चरण धोते हैं, भोजन कराते हैं और श्रद्धा से उसका आशीर्वाद लेते हैं। आखिर क्यों?

क्योंकि,सनातन परंपरा केवल मूर्ति में शक्ति देखने की बात नहीं करती। वह जीवन में शक्ति को पहचानने की शिक्षा भी देती है। कुमारी पूजन से जुड़ी परंपराओं में महाकाली के कन्या रूप में प्रकट होकर कोलासुर के वध की कथा आती है। कथा के अनुसार कोलासुर अत्यंत शक्तिशाली असुर था। देवता उसकी शक्ति के सामने असहाय हो गए और उन्होंने महाकाली की शरण ली।

तब देवी ने भयंकर रूप धारण करने के बजाय एक छोटी कन्या का रूप धारण किया और कोलासुर के सामने पहुंचीं। कोलासुर ने उस बालिका को कमजोर समझा। लेकिन वही कन्या आगे चलकर अपना वास्तविक



■ औघड़ पवानरामजी (पवनानंद नाथ)
श्री महाकाली दरबार दस महाविद्या शक्ति पीठ ,आर्य नगर भिलाई

स्वरूप प्रकट करती है और उसका अंत करती है।

कथा का संदेश देती है–

शक्ति हमेशा विराट रूप में दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं। कभी वह दुर्गा बनकर सामने आती है। कभी महाकाली बनकर। और कभी एक मासूम कन्या के रूप में। इसलिए किसी को उसके बाहरी रूप, उम्र या शारीरिक सामर्थ्य से कमजोर समझ लेना भूल हो सकती है।

मगर कुमारी पूजन का अर्थ केवल एक दिन किसी बालिका के चरण धो देना नहीं है। यदि हम नवरात्रि में कन्या को देवी मानते हैं, तो पूरे वर्ष उसके सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा और स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भी हमारी है।

एक छोटी-सी बच्ची के भीतर पूरा भविष्य छिपा है। वही आगे चलकर डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षिका, कलाकार, अधिकारी, उद्यमी या समाज की किसी भी दिशा में योगदान देने वाली शक्ति बन सकती है। इसलिए कन्या को कमजोर समझना केवल उसे छोटा समझना नहीं है—यह उसके भीतर छिपी संभावनाओं को छोटा समझना है।

कुमारी पूजन का वास्तविक अर्थ तब पूरा होगा जब हम कन्या के चरणों में फूल रखने के साथ-साथ उसके सपनों को भी सम्मान देंगे। अगर उसे देवी कहते हैं, तो उसके अधिकारों की रक्षा भी करनी होगी। अगर उसमें शक्ति देखते हैं, तो उसे अपने निर्णय लेने का अवसर भी देना होगा।

नवरात्रि के नौ दिनों में कन्या को देवी मानना आसान है। उसके चरणों में फूल रखना और उसे भोजन कराना भी आसान है। लेकिन असली परीक्षा नवरात्रि समाप्त होने के बाद शुरू होती है। क्या हमारी दृष्टि तब भी वही रहती है?

अगर हम कन्या के चरण पूजते हैं, तो उसके सपनों का भी सम्मान करना होगा। अगर उसे देवी कहते हैं, तो उसकी सुरक्षा और शिक्षा की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। अगर उसमें शक्ति देखते हैं, तो उसे कमजोर समझकर रोकना भी नहीं चाहिए।

यही कुमारी पूजन का वास्तविक संदेश है। और यही महाकाली की कथा की सबसे बड़ी सीख भी है—शक्ति को उसके बाहरी रूप से मत आंकिए।

शक्ति हमेशा विराट रूप में दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं। कभी वह दुर्गा बनकर सामने आती है। कभी महाकाली बनकर। और कभी एक मासूम कन्या के रूप में। इसलिए किसी को उसके बाहरी रूप, उम्र या शारीरिक सामर्थ्य से कमजोर समझ लेना भूल हो सकती है।

जब कन्या पूजन करें, तो केवल परंपरा निभाने के लिए उसके सामने सिर न झुकाएं। बल्कि इस भाव से झुकें– 'तुममें वही शक्ति है, जिसे हम माँ दुर्गा और माँ काली के रूप में पूजते हैं।'



इसलिए इस बार जब आप अखंड ज्योति के सामने बैठें, तो उसे केवल एक दीपक की तरह मत देखिए। उसे उस तेजोमय शक्ति की स्मृति के रूप में देखिए, जिसने अनेक देवताओं की अलग-अलग शक्तियों को एक विराट शक्ति में बदल दिया था।

और जब कन्या पूजन करें, तो केवल परंपरा निभाने के लिए उसके सामने सिर न झुकाएं। बल्कि इस भाव से झुकें– 'तुममें वही शक्ति है, जिसे हम माँ दुर्गा और माँ काली के रूप में पूजते हैं।'

फिर स्वयं से एक प्रश्न पूछिए– 'मेरे पास ऐसा क्या है, जिसे मैं किसी और के जीवन में प्रकाश बनाने के लिए दे सकता हूं?'

क्योंकि शक्ति को अपने भीतर बंद करके रखना शक्ति नहीं है। शक्ति तब बनती है, जब वह किसी और के काम आती है। और शायद नवरात्रि की अखंड ज्योति और कन्या पूजन हमें यही संदेश देता है—

दीपक की तरह जलिए। देवी की तरह शक्ति बनिए। कन्या में शक्ति पहचानिए। और अपने हिस्से का प्रकाश किसी और के जीवन तक पहुंचाइए।

'कन्या का सम्मान, शक्ति का सम्मान है। नारी का सम्मान, सृष्टि की मूल शक्ति का सम्मान है'

संदर्भः औघड़ पवानरामजी (पवनानंद नाथ)
श्री महाकाली दरबार दस महाविद्या शक्ति पीठ आर्य नगर भिलाई

लेखन-संपादन एवं प्रस्तुति-
डॉ. नरेन्द्र पाण्डेय
संपादक, लाईफ वर्सिटी





शेरनियों की दहाड़

सवाल सत्ता से, आंदोलन से भी

इस कहानी को केवल नायिकाओं और खलनायकों में बांटकर देखना पर्याप्त नहीं होगा। सरकार से सवाल होने चाहिए, पुलिस से जवाब मांगा जाना चाहिए और आंदोलनकारियों से भी पूछा जाना चाहिए कि वे जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, उसके प्रति उनकी अपनी जवाबदेही क्या है।

डॉ. नरेन्द्र पाण्डेय

धरती पर जब दबाव बढ़ता है, तो कभी-कभी उसकी भीतरी ऊर्जा ज्वालामुखी बनकर बाहर निकलती है। लावा अपने रास्ते में बहुत कुछ बदल देता है। ठंडा होने के बाद ज्वालामुखीय पदार्थ मिट्टी को खनिजों से समृद्ध भी कर सकते हैं। समाज में लंबे समय तक दबाई गई आवाजें भी कभी-कभी इसी तरह प्रतिरोध बनकर सामने आती हैं। लेकिन हर विस्फोट अपने आप उपजाऊ जमीन नहीं बनाता। बदलाव इस बात पर निर्भर करता है कि उस ऊर्जा को किस दिशा में ले जाया जाता है।

जुलाई से अक्टूबर 2026 के बीच युवा आंदोलनों और राजनीतिक प्रदर्शनों में सामने आई महिलाओं के साहस को भी इसी संदर्भ में देखने की जरूरत है। नेहा बोरा, रिया आहिर, रत्ना सिंह, नेहा सिंह राठौर और अन्य महिलाओं से जुड़ी घटनाओं ने शिक्षा, नागरिक अधिकार, पुलिस कार्रवाई और सत्ता से सवाल पूछने की आजादी जैसे मुद्दों को सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाया है।

इन महिलाओं की कहानियों में एक साझा सूत्र दिखाई देता है—सवाल पूछने का साहस। लेकिन इस कहानी को केवल नायिकाओं और खलनायकों में बांटकर देखना पर्याप्त नहीं होगा। सरकार से सवाल होने चाहिए, पुलिस से जवाब मांगा जाना चाहिए और आंदोलनकारियों से भी पूछा जाना चाहिए कि वे जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, उसके प्रति उनकी अपनी जवाबदेही क्या है।

जब लड़की पुलिस की गाड़ी के सामने खड़ी होती है

रिया आहिर से जुड़ी घटना ने एक महत्वपूर्ण सवाल सामने रखा—अगर किसी प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया जा रहा है, तो क्या नागरिक यह पूछ सकता है कि गिरफ्तारी किस आधार पर हुई और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं? बिल्कुल पूछ सकता है। पुलिस के पास कानून लागू करने और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन वह भी कानून से ऊपर नहीं है। गिरफ्तारी और हिरासत की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन होना चाहिए। यहां पुलिस से सवाल है—कार्रवाई का आधार क्या था? क्या संबंधित व्यक्ति को आवश्यक जानकारी दी गई? क्या प्रक्रिया कानून के अनुरूप थी?

लेकिन दूसरा सवाल भी जरूरी है। क्या किसी वायरल वीडियो के कुछ सेकंड देखकर पूरे घटनाक्रम का फैसला सुनाया जा सकता है? पुलिस का पक्ष सुने बिना उसे दोषी ठहराना भी उचित नहीं। आरोपों की जांच पूरी जानकारी और प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए। पुलिस की जवाबदेही का अर्थ पुलिस के हर



राहुल-प्रियंका का विरोध और चुनाव आयोग पर सवाल

अक्टूबर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं के प्रदर्शन ने चुनावी पारदर्शिता का प्रश्न फिर चर्चा में ला दिया। विपक्ष ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग तक मार्च करने की कोशिश की। 6 अक्टूबर को दिल्ली में मार्च रोके जाने के बाद कई विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। विपक्ष ने मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चिंता जताई।यहां सवाल केवल किसी एक आयुक्त के इस्तीफे का नहीं है। असली सवाल उस भरोसे का है, जिस पर लोकतंत्र की पूरी इमारत खड़ी है।

मतदाता सूची में किसी योग्य नागरिक का नाम छूट जाए, तो उसके लिए यह महज प्रशासनिक गलती नहीं, मताधिकार से वंचित होने की आशंका है। दूसरी ओर, मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन रखना भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसलिए जरूरी है कि नाम हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी हो, नागरिकों को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिले और शिकायतों का प्रभावी निवारण हो। विपक्ष ने स्क्रूक को लेकर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष रखा है। किसी आरोप को बिना जांच अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं, लेकिन गंभीर सवालों को केवल राजनीतिक आरोप बताकर खारिज कर देना भी पर्याप्त जवाब नहीं है।

सरकार से सवाल है–चुनावी प्रक्रिया पर संदेह दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? चुनाव आयोग से सवाल है–क्या मतदाता सूची से जुड़े विवादों पर पर्याप्त पारदर्शिता के साथ जवाब दिया जा रहा है ?लेकिन विपक्ष से भी सवाल जरूरी है। क्या आरोपों के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण हैं? क्या आंदोलन का लक्ष्य केवल ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा है, या ऐसी व्यवस्था बनाना भी है जिसमें किसी योग्य मतदाता को अपना नाम सूची में बनाए रखने के लिए संघर्ष न करना पड़े? कदम को गलत मान लेना नहीं है। उसी तरह वर्दी का सम्मान करने का अर्थ यह भी नहीं कि नागरिक सवाल पूछना छोड़ दे।

शिक्षा और युवाओं के भविष्य का सवाल

नेहा बोरा से जुड़े आंदोलन के संदर्भ में शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा और पेपर लीक जैसे मुद्दे सामने आते हैं। युवाओं के लिए ये केवल राजनीतिक विषय नहीं हैं। इनके साथ उनका समय, पैसा, परिवार की उम्मीदें और भविष्य जुड़ा होता है। अगर परीक्षा में अनियमितता की शिकायत आती है, पेपर लीक का आरोप लगता है या भर्ती प्रक्रिया लंबे समय तक अधर में रहती है, तो नुकसान केवल एक परीक्षा का नहीं होता। व्यवस्था पर भरोसा भी कमजोर पड़ता है।

सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराए, भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए और दोषियों के खिलाफ प्रमाणों के आधार पर कार्रवाई करे। लेकिन आंदोलनकारियों से भी सवाल है—क्या उनके पास लगाए गए आरोपों के ठोस प्रमाण हैं? क्या उनकी मांगों में समाधान की स्पष्ट रूपरेखा है? क्या वे उन छात्रों की आवाज भी सुन रहे हैं जिनकी प्राथमिकता जल्द से जल्द परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया पूरी होना है? इन सवालों का उद्देश्य आंदोलन को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे प्रभावी बनाना है। असली सफलता केवल किसी मंत्री के इस्तीफे से नहीं मापी जाएगी। सफलता तब होगी, जब परीक्षा प्रणाली अधिक भरोसेमंद बने और किसी छात्र को अपने भविष्य के लिए बार-बार सड़क पर उतरने की मजबूरी न हो।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का रास्ता क्या है?

यहां एक बुनियादी संवैधानिक सवाल भी है। क्या प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा सकते हैं? नहीं। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने जैसी है। सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में निर्धारित विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना और उसके बाद राष्ट्रपति का आदेश आवश्यक होता है। प्रधानमंत्री अकेले उन्हें नहीं हटा सकते। आम बोलचाल में इसे महाभियोग कहा जाता है, हालांकि संवैधानिक रूप से यह न्यायाधीश को हटाने जैसी प्रक्रिया है। तो फिर सवाल उठता है—जब सड़क पर प्रदर्शन से ज्ञानेश कुमार सीधे पद

से नहीं हटेंगे और प्रधानमंत्री के पास भी उन्हें अकेले हटाने का अधिकार नहीं है, तब यह आंदोलन क्यों?

क्या उद्देश्य जनमत तैयार करना है? क्या विपक्ष चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार और जवाबदेही की मांग कर रहा है? क्या इस्तीफे की मांग किसी ठोस संवैधानिक रणनीति का हिस्सा है, या मुख्य रूप से राजनीतिक दबाव बनाने का तरीका?इन सवालों का जवाब विपक्ष को देना चाहिए। हालांकि संवैधानिक प्रक्रिया कठिन होने का अर्थ यह नहीं कि आंदोलन का कोई महत्व नहीं। प्रदर्शन किसी मुद्दे को सार्वजनिक विमर्श में ला सकता है, संस्थाओं से जवाब मांग सकता है और राजनीतिक दबाव बना सकता है। लेकिनराजनीतिक दबाव और संवैधानिक कार्रवाई दो अलग-अलग चीजें हैं।

विपक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि उसके आरोप किन विशिष्ट आधारों पर टिके हैं और उन्हें साबित करने की योजना क्या है। वहीं सरकार और चुनाव आयोग को भी शिकायतों का पारदर्शी जवाब देना चाहिए। चुनावी विश्वसनीयता किसी एक दल की संपत्ति नहीं, पूरे लोकतंत्र का प्रश्न है।

महिलाओं का साहस–सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं

इन आंदोलनों में युवा महिलाओं की भागीदारी का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि वे किसी सरकार या राजनीतिक विचारधारा का विरोध कर रही हैं। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या वे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को लेकर बनी पुरानी धारणाओं को बदल रही हैं? हमारे समाज में लड़की से अक्सर कहा जाता है—बहुत मत बोलो, विवाद में मत पड़ो, राजनीति तुम्हारा काम नहीं है। परिवार की इज्जत और सुरक्षा की चिंता कई बार इस सलाह का हिस्सा होती है। लेकिन सुरक्षा का समाधान महिलाओं को चुप करा देना नहीं हो सकता।

यहां एक प्रश्न उठता है= क्या हम महिलाओं के साहस का सम्मान तभी करते हैं, जब वे हमारे राजनीतिक विचारों के पक्ष में खड़ी हों? यदि किसी महिला की मांग हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती, तो क्या हम उसके अधिकारों को कम महत्वपूर्ण मानने लगते हैं? महिला की स्वतंत्रता का अर्थ केवल विरोध प्रदर्शन में भाग लेने की आजादी नहीं है। इसका अर्थ घर, विश्वविद्यालय, कार्यस्थल, पंचायत और संसद में बराबरी से अपनी बात रखने का अधिकार भी है।

ज्वालामुखी के बाद कैसी जमीन बनेगी?

लंबे समय से जमा असंतोष को केवल अव्यवस्था कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। उसके पीछे वास्तविक शिकायतें, अधूरे वादे और संस्थागत कमियां हो सकती हैं। लेकिन हर विस्फोट अपने आप उपजाऊ जमीन नहीं बनाता। बदलाव के लिए ऊर्जा के साथ विवेक, आक्रोश के साथ दिशा और साहस के साथ तथ्य भी चाहिए। सरकार को आलोचना से बचने के बजाय कमियों को पहचानना चाहिए। पुलिस को अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। चुनाव आयोग को पारदर्शिता से भरोसा मजबूत करना चाहिए। आंदोलनकारियों को अपने साहस को प्रमाण, स्पष्ट मांगों और समाधान में बदलना चाहिए।

लोकतंत्र किसी एक पक्ष की जीत का नाम नहीं है। सरकार गलत हो सकती है, आंदोलन गलत हो सकता है और मीडिया भी अधूरा सच दिखा सकता है। इसलिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत किसी एक व्यक्ति या विचारधारा की अचूकता नहीं, बल्कि सवाल पूछने, प्रमाण जांचने और गलती सुधारने की क्षमता है।आज कोई लड़की पुलिस के सामने अपने अधिकार पूछती है, कोई छात्रा परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, कोई लोकगायिका गीत के जरिए सत्ता से जवाब मांगती है और कोई महिला नेता चुनावी पारदर्शिता के लिए प्रदर्शन करती है—तो यह लोकतंत्र के जीवंत होने का संकेत हो सकता है। लेकिन उस संकेत को स्थायी बदलाव में बदलने की जिम्मेदारी सभी की है।

सत्ता को याद रखना होगा कि बहुमत जवाबदेही से मुक्ति नहीं देता। आंदोलनकारियों को याद रखना होगा कि विरोध का अधिकार तथ्यों और जिम्मेदारी से अलग नहीं है। और समाज को तय करना होगा कि वह साहसी महिलाओं को केवल वायरल तस्वीरों में सराहेगा या उनके समान अधिकारों को रोजमर्रा के जीवन में भी स्वीकार करेगा।



बाहर की दुनिया जीतने से पहले खुद को समझो



रायपुर। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों, करियर और सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने में जुटा है, लेकिन इसी दौड़ के बीच एक बुनियादी सवाल पीछे छूटता जा रहा है—क्या हम वास्तव में खुद को समझते हैं? इसी सवाल को केंद्र में रखते हुए रायपुर में आयोजित दो अलग-अलग कार्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परंपरा, आधुनिक विज्ञान, व्यक्तित्व विकास और युवाओं की बदलती जीवनशैली पर गंभीर चर्चा हुई।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को 'स्वयं से साक्षात्कार' विषय पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को केवल बाहरी दुनिया और पेशेवर जिम्मेदारियों तक सीमित न रखते हुए अपने भीतर की ऊर्जा, मन, चेतना और व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को समझने के लिए प्रेरित करना था।

कार्यक्रम में स्वामी महेश ने भारतीय ज्ञान परंपरा में वर्णित अपरा विद्या और परा विद्या की अवधारणा को समझाया। उन्होंने कहा कि अपरा विद्या उस ज्ञान से संबंधित है जिसे इंद्रियों के माध्यम से देखा, पढ़ा और समझा जा सकता है, जबकि परा विद्या आंतरिक और सूक्ष्म अनुभूति से जुड़ी मानी जाती है। उन्होंने मानव अस्तित्व को केवल भौतिक शरीर तक सीमित न मानते हुए पंचकोश—अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय की अवधारणा पर भी प्रकाश डाला।

वहीं डॉ. अनिल गुप्ता ने ऊर्जा, चेतना, षट्चक्र और आभामंडल जैसे विषयों को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि भारतीय परंपरा में लंबे समय से मानव शरीर, मन और आंतरिक ऊर्जा के बीच संबंध को लेकर चिंतन किया जाता रहा है।

इस कार्यशाला में आयोग के सदस्य विवेक गनोदवाले, सचिव सूर्यप्रकाश शुक्ला तथा पावर कंपनीज़ के प्रबंध निदेशक एस.के. कटियार, राजेश कुमार शुक्ला और भीम सिंह कंवर सहित अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन उपमहाप्रबंधक जनसंपर्क गोविन्द पटेल ने किया।

इसी विचार को युवाओं के बीच ले जाने के उद्देश्य सेएमिटी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फार्मेसीमें भी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां चर्चा का केंद्र युवा पीढ़ी, व्यक्तित्व और बदलती जीवनशैली रही।

डॉ. अनिल गुप्ता ने Neuro-Linguistic Programming (NLP) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्ट व्यक्तित्व प्रवृत्ति होती है। कोई व्यक्ति Visual होता है और चीजों को देखकर बेहतर समझता है, कोई Auditory होता है जो सुनकर चीजों को ग्रहण करता है, जबकि Kinesthetic व्यक्ति अनुभव और महसूस करके सीखता है। उनका कहना था कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसकी व्यक्तित्व प्रवृत्ति को समझना जरूरी है।







कार्यक्रम में लाईफ वर्सिटी के संपादक डॉ नरेन्द्र पाण्डेय ने युवाओं की मौजूदा चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि आज की Gen-Z के पास सूचना की कमी नहीं है, लेकिन दिशा का संकट जरूर दिखाई देता है। सोशल मीडिया से लगातार जानकारी हासिल करने वाली यह पीढ़ी बाहरी व्यक्तित्व को निखारने के लिए अनेक प्रयास करती है, लेकिन अपनी आंतरिक दुनिया को समझने का अवसर कम मिलता है।

उन्होंने युवाओं में बढ़ते नशे और एडिक्शन को भी गंभीर चुनौती बताया। उनका कहना था कि समस्या केवल शराब या अन्य नशीले पदार्थों तक सीमित नहीं है, बल्कि मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल भी एक तरह की निर्भरता पैदा कर रहा है। इसके साथ ही कम उम्र में डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी जीवनशैली संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं।

डॉ नरेन्द्र पाण्डेय ने NLP की व्यक्तित्व प्रवृत्तियों को भारतीय आयुर्वेद की वात, पित्त और कफ अवधारणा से जोड़ते हुए कहा कि हमारे आसपास अलग-अलग स्वभाव और व्यवहार वाले लोग मौजूद हैं। किसी को समझने से पहले उसके स्वभाव और अपनी प्रतिक्रिया को समझना जरूरी है।

दोनों कार्यक्रमों का मूल संदेश एक ही रहा—दूसरों को समझने और दुनिया को बदलने की कोशिश से पहले व्यक्ति को स्वयं से संवाद करना होगा। आखिर सवाल यही है कि जब हम खुद को नहीं समझते, तो दूसरों को और अपने आसपास की दुनिया को कितनी गहराई से समझ पाएंगे?

Positive Health Zone
Unique Wellbeing Center
छोटा सा कैमरा, जो बताए
स्वास्थ्य का भविष्य
Advance Kirlian Photography
हमारे शरीर में सात चक्र होते हैं, GDV कैमरा की मदद से हमारे में अब सातों चक्रों एवं AURA को देखना हुआ आसान
Advantages of GDV :
1. Stress Level Analysis
2. Life Force Energy Analysis At Aura, Chakra Nadis And Organ Level.
3. Energy Balance In Organs
4. Chakras Energy & Alignment Analysis
5. Blockages In Major Nadi's
6. Functional And Energetic Condition Of Organs And Organ System
7. Personalised Biocore Bineural Beat Frequency Music Based On Your Gdv To Align Your Chakras And Balance Your Life Force Energy
PRE
POST
www.phzinfo.com 9109185025, 9109185028
A-41, Amrapali Society, Near Ganga Diagonostic, Dhamtari Road, Pachpedi Naka, Raipur, C.G.

स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं कागजों पर और मरीज जमीन में

मेकाहारा से HLL तक उठते सवाल



मेकाहारा की अधूरी परियोजनाओं से HLL को पैथोलॉजी का काम सौंपने तक सवालों के घेरे में व्यवस्था—सरकार का दावा है कि जांचों की संख्या बढ़ेगी, विपक्ष प्रक्रिया और खर्च पर सवाल उठा रहा है; आखिर स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय सचिव की जवाबदेही कहां तय होगी?

लाईफ वर्सिटी

किसी सरकारी अस्पताल की सबसे बड़ी पहचान उसकी इमारत नहीं होती। उसकी पहचान उस मरीज से होती है, जिसे वहां पहुंचने के बाद यह भरोसा हो कि बेड मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा, जरूरी जांच होगी और इलाज समय पर शुरू होगा। लेकिन जब यही बुनियादी भरोसा टूटने लगे तो सवाल केवल अस्पताल प्रशासन पर नहीं उठता। सवाल उस पूरी व्यवस्था पर उठता है, जिसके शीर्ष पर स्वास्थ्य विभाग का राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व बैठा है।

रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल से जुड़ी तस्वीर इसी असहज सवाल को सामने रखती है। करीब 322 करोड़ रुपये की 700 बिस्तरों वाली परियोजनाहो या कैंसर विभाग, सिकल सेल संस्थान, परिजन निवास और हेमेटोलॉजी जैसी योजनाएं—घोषणाएं और प्रस्ताव अपनी जगह हैं, लेकिन मरीज तक सुविधा पहुंचने का इंतजार खत्म नहीं हुआ।

दूसरी ओर सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में लैब जांचों के संचालन और प्रस्तावित दरों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यानी एक तरफसुविधाएं बढ़ाने वाली परियोजनाएं लंबित हैं, दूसरी तरफ उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की लागत और प्रक्रिया पर बहस हो रही है।यहीं से वह सवाल पैदा होता है, जिसे अब टालना मुश्किल है—क्या स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं मरीज के लिए हैं या फाइलों में प्रगति दिखाने के लिए?

सरकार का तर्क है कि नई व्यवस्था से जांचों की संख्या और सुविधाएं बढ़ेंगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी कहा है कि प्रक्रिया नियमानुसार पूरी हुई है और यदि कहीं गड़बड़ी मिलती है तो जांच कर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता।

अगर व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए खर्च बढ़ रहा है, तो उसका लाभ मरीज तक कब और कैसे पहुंचेगा? और अगर पुरानी व्यवस्था में कमियां थीं, तो उनकी जवाबदेही किसकी थी?

भूमिपूजन के बाद मरीज को क्या मिला?

सरकारी व्यवस्था में किसी परियोजना की शुरुआत अक्सर भूमिपूजन से होती है। तस्वीरें आती हैं, घोषणाएं होती हैं, लागत बताई जाती है और उम्मीद जगती है कि अब अस्पताल की क्षमता बढ़ेगी।लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में भूमिपूजन अंतिम उपलब्धि नहीं, बल्कि काम की शुरुआत है।

मेकाहारा प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी चिकित्सा संस्थानों



मरीज अस्पताल क्यों छोड़ रहें है?

अस्पताल से जुड़ा एक और आंकड़ा और भी गंभीर सवाल पैदा करता है। रिपोर्ट के अनुसार, हर महीने औसतन 80 से अधिक मरीज LAMA—Left Against Medical Advice के तहत इलाज अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। एक संवेदनशील स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए यह प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि मरीज अस्पताल छोड़कर क्यों जा रहा है? क्या उसे बेड नहीं मिला?क्या जांच में देरी हुई ?क्या इलाज लंबा खिंच गया? क्या परिजनों को पर्याप्त जानकारी नहीं मिली? क्या आर्थिक कारण सामने आया? अगर विभाग के पास इन सवालों का डेटा नहीं है, तो यह अपने आप में एक कमी है। और अगर डेटा है, तो उस आधार पर सुधार की कार्रवाई कहां है?

में है। यहां छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों से मरीज इलाज के लिए आते हैं। स्वाभाविक है कि बढ़ते मरीजों के दबाव के साथ अस्पताल की क्षमता भी बढ़नी चाहिए इसी जरूरत के तहत700 बिस्तरों वाले नए अस्पताल की परियोजनासामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी लागत करीब 322 करोड़ रुपए बताई गई। लेकिन सवाल यह है कि जिस परियोजना से मरीजों को अतिरिक्त बेड और सुविधाएं मिलनी हैं, वह अब तक पूरी तरह जमीन पर क्यों नहीं उतर सकी ?

इसके अलावा कैंसर वार्ड, सिकल सेल संस्थान, हेमेटोलॉजी और परिजन आवास जैसी योजनाओं की स्थिति भी सवाल खड़े करती है। तब एक बुनियादी प्रशासनिक सवाल बनता है—देरीकिस स्तर पर हुई? फाइल कहां अटकी ? निर्माण की समयसीमा क्या थी? किस अधिकारी को इसकी निगरानी करनी थी? देरी के लिए किससे जवाब मांगा गया ? और सबसे महत्वपूर्ण—क्या किसी की जवाबदेही तय हुई ?सरकार को इन सवालों का जवाब सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति से नहीं, बल्कि समयसीमा और दस्तावेजों के साथ देना चाहिए।

HLL की कहानी–सुविधा बढ़ेगी या खर्च?

आज चिकित्सा व्यवस्था में जांच इलाज की दिशा तय करती है। डॉक्टर की सलाह के बाद CBC, विटामिन, हार्मोन, बायोकेमिकल और दूसरी जांचें मरीज के उपचार का आधार बनती हैं ऐसे में सरकारी अस्पतालों में जांच सुविधा का सस्ता, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण होना बेहद जरूरी है।

सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी सेवाओं के संचालन और विस्तार का जिम्मा HLL Lifecare को देने का फैसला हुआ। HLL Lifecare केंद्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। छत्तीसगढ़ में इसे लेकर विवाद मुख्यत: इस बात पर है कि राज्य ने यह काम किस प्रक्रिया के तहत सौंपा और इसकी लागत क्या होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में HLL को लैब संचालन का काम दिया गया, जबकि मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों में कंपनी को प्रतिस्पर्धी टेंडर के बाद अलग-अलग स्तर की छूट मिली। छत्तीसगढ़ में कथित रूप से कम डिस्काउंट पर काम मिलने और लंबी अवधि के अनुबंध को लेकर सवाल उठाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल जांचों की दरों पर है। उदाहरण के लिए रिपोर्ट में CBC की पुरानी दर रू.45 और नई प्रस्तावित दर रू.197 बताई गई है। विटामिन D की दर रू. 277 से रू. 847, B12 की रू.138 से रू. 657 और ग्लूकोज की रू.22 से रू.197 तक होने का उल्लेख है। अगर ये दरें लागू होती हैं तो सवाल स्वाभाविक है—क्या जांचों की संख्या बढ़ने के साथ खर्च भी कई गुना बढ़ जाएगा ?और अगर सरकार कहती है कि यह खर्च मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए है, तो उसका परिणाम मापने का पैमाना क्या होगा ?

सरकार का पक्ष

खर्च थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन जांचें भी बढ़ेंगी

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल



का बयान इस विवाद में महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की गई है और उसी के अनुसार काम दिया गया है। मंत्री के अनुसार, एजेंसी को काम देने से कुछ अतिरिक्त खर्च जरूर होगा, लेकिनटेस्ट की संख्या भी बढ़ेगी और लोगों को होने वाली असुविधा से बचाया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलती है तो मामले की जांच कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

लेकिन यहीं से अगला सवाल पैदा होता है—अगर जांचों की संख्या बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? कितने मरीजों को इसका लाभ मिलेगा? नई व्यवस्था की प्रति जांच लागत और पुरानी व्यवस्था की वास्तविक लागत क्या है? और क्या सरकार इस पूरे मॉडल का वार्षिक Outcome Audit सार्वजनिक करेगी ?

मामला अदालत तक भी पहुंचा।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में HLL को नामांकन के आधार पर काम दिए जाने को चुनौती दी गई। याचिका में खुली प्रतिस्पर्धी निविदा के बजाय nomination basis पर काम देने पर सवाल उठाए गए, जबकि राज्य की ओर से तर्क दिया गया कि विशेष और समय-संवेदी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लागू नियमों में अपवाद की गुंजाइश है और HLL की विशेषज्ञता को देखते हुए निर्णय लिया गया।यानी यहां दो पक्ष साफ हैं—एक तरफ प्रक्रिया पर सवाल, दूसरी तरफ सार्वजनिक हित और विशेषज्ञता का सरकारी तर्क।

डॉ. विवेक चौधरी- नई व्यवस्था के साथ अस्पताल विस्तार का दावा



मेकाहारा के डीनडॉ. विवेक चौधरीने अस्पताल की लंबित परियोजनाओं को लेकर सकारात्मक तस्वीर सामने रखी है।उनके अनुसार, 700 बिस्तरों वाले नए अस्पताल का निर्माण पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराया जा रहा है। कैंसर वार्ड का कार्य भी जल्द शुरू होगा और परिजन आवास के लिए एनजीओ के साथ समझौता किया गया है।यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि विभाग इन योजनाओं को मृत या बंद परियोजनाएं नहीं मान रहा, बल्कि उनके आगे बढ़ने का दावा कर रहा है। लेकिन 'जल्द' का मतलब कब? अगर कैंसर वार्ड जल्द शुरू होना है तो उसकी समयसीमा क्या है? 700 बेड की परियोजना कब पूरी होगी? परिजन आवास कब उपलब्ध होगा? योजना की घोषणा और उसके वास्तविक उपयोग के बीच की दूरी ही आखिर किसी सरकारी योजना की सफलता या असफलता तय करती है।

स्वास्थ्य सचिव की जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी

राजनीतिक नेतृत्व नीति और प्राथमिकता तय करता है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर योजनाओं को जमीन पर उतारने की



जिम्मेदारी विभागीय तंत्र की होती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग के सचिव से भी सवाल बनता है।

HLL का चयन किस आधार पर हुआ? क्या विभाग ने लागत और गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन किया? क्या पुराने सरकारी संसाधनों का पूरा आकलन किया गया? सरकारी लैब में उपलब्ध मशीनों, रीजेंट और प्रशिक्षित कर्मचारियों का क्या होगा? नई व्यवस्था में सरकारी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की भूमिका क्या होगी? किस परियोजना की मॉनिटरिंग किस

स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से सवाल यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि योजनाएं कितनी बनीं, बल्कि यह कि जो योजनाएं बनीं, वे मरीज तक कब पहुंचीं। क्योंकि अंततः किसी भी सरकार की स्वास्थ्य नीति की सफलता फाइल पर लगी मंजूरी की मुहर से नहीं, अस्पताल के बेड पर मिले इलाज से तय होती है।

स्तर पर हो रही है? लंबित परियोजनाओं की साप्ताहिक या मासिक समीक्षा का क्या सिस्टम है? टेंडर से लेकर निर्माण तक प्रत्येक चरण की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है? देरी होने पर क्या कारण दर्ज किए जाते हैं? और सबसे अहम—क्या स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसा कोई सार्वजनिक डैशबोर्ड है, जहां आम नागरिक देख सके कि उसके जिले की कौन-सी स्वास्थ्य योजना कितनी आगे बढ़ी?अगर ऐसा सिस्टम नहीं है तो इसे अब बनाना चाहिए।

यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने HLL व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों के भविष्य पर चिंता जताई है और मंत्री तथा स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात भी की थी। संघ के अनुसार, उसे बताया गया कि HLL अपने कर्मचारी और संसाधन स्वयं रखेगा तथा प्रभावित सरकारी MLT को दूसरी जगह प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।

बजट खर्च होना और स्वास्थ्य सेवा मिलना–दो अलग बातें हैं

स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ना अच्छी बात है। नई योजनाएं आना भी जरूरी है। लेकिन किसी योजना पर पैसा स्वीकृत होना और मरीज को उसका लाभ मिलना दो अलग-अलग बातें हैं। बजट Input है, परिणाम Outcome है। एक अस्पताल बन गया लेकिन डॉक्टर नहीं हैं—तो परिणाम क्या? मशीन खरीद ली गई लेकिन तकनीशियन नहीं है—तो परिणाम क्या? जांच की दर बढ़ गई लेकिन रिपोर्ट समय पर नहीं मिली—तो परिणाम क्या? 700 बेड की योजना स्वीकृत है लेकिन बेड उपलब्ध नहीं—तो मरीज को लाभ कब मिला ?यही वह बदलाव है जिसकी जरूरत स्वास्थ्य प्रशासन में है—घोषणा आधारित व्यवस्था से परिणाम आधारित व्यवस्था की ओर।

कागज से अस्पताल तक कब पहुंचेगी योजना?

मेकाहारा की लंबित परियोजनाएं और HLL से जुड़ा पैथोलॉजी विवाद अलग-अलग घटनाएं दिखाई दे सकती हैं, लेकिन दोनों एक ही बीमारी की ओर संकेत करते हैं—नीति और क्रियान्वयन के बीच की दूरी। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का मूल्यांकन अब इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कितनी फाइलें बनीं, कितने बजट स्वीकृत हुए या कितने भूमिपूजन हुए। मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि—कितने मरीजों को समय पर बेड मिला? कितनी जांचें सस्ती और समय पर उपलब्ध हुईं? कितने मरीजों को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल नहीं जाना पड़ा? कितनी लंबित परियोजनाएं समय पर पूरी हुईं? और सबसे महत्वपूर्ण—क्या आम नागरिक का सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा?

यही वह सवाल है, जिसका जवाब आंकड़ों से ज्यादा अस्पताल के वार्ड में मिलता है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के सामने अब चुनौती नई योजना घोषित करने की नहीं है। चुनौती उन योजनाओं कोकागज से निकालकर अस्पताल की जमीन तक पहुंचाने की है। और जब करोड़ों रुपये की परियोजनाएं लंबित हों, मरीज सुविधाओं के लिए इंतजार कर रहा हो और जांच व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हों, तबजवाबदेही मांगना राजनीति नहीं—लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा है।



शराब दुकान से Smart Governance तक

शराब की दुकान आम आदमी के लिए शायद सिर्फ खरीद-बि ी की जगह हो, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा प्रशासनिक और तकनीकी तंत्र काम करता है। सप्लाई चेन से लेकर स्टॉक, बिलिंग, बैंकिंग, कैश मैनेजमेंट और उपभोक्ता शिकायतों तक-हर स्तर पर एक मजबूत सिस्टम की जरूरत होती है। इस पूरी व्यवस्था में एक छोटी-सी गड़बड़ी भी सवाल खड़े कर सकती है और एक बेहतर सिस्टम पारदर्शिता तथा जवाबदेही को नई दिशा दे सकता है। आज CSMCL सिर्फ शराब की बिक्री से जुड़ी संस्था के रूप में नहीं, बल्कि technology, data और governance के बदलते दौरमें एक बड़े operational system के रूप में चर्चा में है। इसी बदलती व्यवस्था को समझने के लिए लाइफ वर्सिटी ने CSMCL के एमडी से बातचीत की। बातचीत में टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से लेकर एमआरपी, ओवर-रेट, कैश मैनेजमेंट, एआई, उपभोक्ता अधिकार और सामाजिक जिम्मेदारी तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।



CSMCL के MD पदुम सिंह एल्मा से लाईफ वर्सिटीके संपादक डॉ नरेन्द्र पाण्डेय की– AI, MRP, डिजिटल सिस्टम, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी पर खुली बातचीत --

लाईफ वर्सिटी- आम तौर पर लोग CSMCL को सिर्फ शराब की दुकानों के संचालन से जोड़कर देखते हैं। वास्तव में CSMCL की भूमिका कितनी व्यापक है?

■ **MD:** देखिए, CSMCL की भूमिका केवल रिटेल काउंटर तक सीमित नहीं है। इसके पीछे प्रोक्योरमेंट, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, रिटेल ऑपरेशंस, बिलिंग, बैंकिंग और मॉनिटरिंग जैसी कई प्रक्रियाएं जुड़ी हैं। हमारा प्रयास यही है कि इस पूरी चेन को अधिक ट्रांसपेरेंट, टेक्नोलॉजी-ड्रिवन और अकाउंटेबल बनाया जाए। आज केवल व्यवस्था चलाना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी देखना है कि व्यवस्था कितनी एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रही है।

लाईफ वर्सिटी- शराब के कारोबार में ड्ड की जरूरत आखिर क्यों पड़ी?

■ **MD:** एआई हमारे लिए केवल तकनीकी प्रयोग नहीं है। इसका उद्देश्य डिसीजन-मेकिंग को डेटा-ड्रिवन बनाना है आज किसी भी बड़े डिस्ट्रीब्यूशनसिस्टममें डेटाबहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास अलग-अलग लोकेशन, प्रोडक्ट्स और डिमांड पैटर्न्स से जुड़ा काफी डेटा होता है। AI की मदद से डिमांड को बेहतर तरीके से समझने, इन्वेंट्री प्लानिंग करने और सप्ली चैन में संभावित गैप्स को पहचान करने में मदद मिल सकती है।

लाईफ वर्सिटी- यानी भविष्य में यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि किस क्षेत्र में किस तरह की डिमांड आने वाली है?

■ **MD:** हां, यही इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर किसी विशेष स्थान पर किसी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार एक पैटन दिखाती है, तो उस डेटा का उपयोग इन्वेंटरी प्लानिंगमें किया जा सकता है। इससे एक तरफ जमा अनुपयोगी स्टॉक कम करने में मदद मिलेगी और दूसरी तरफ कमी जैसी स्थिति से भी बचा जा सकता है।

लाईफ वर्सिटी- लेकिन उपभोक्ता के स्तर पर सबसे बड़ा सवाल MRP का है। ओवररेटिंग की शिकायतें आती रही हैं। इस पर आपकी क्या प्राथमिकता है?

■ **MD:** MRP एक स्पष्ट व्यवस्था है और निर्धारित मूल्य से अधिक पर बिक्री नहीं होनी चाहिए। हमारी व्यवस्था में मॉनिटरिंग और शिकायतों के आधार पर कार्रवाई का प्रावधान है। जहां भी नियमों का उल्लंघन सामने आता है, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। हमारा मानना है कि केवल नियम बना देना पर्याप्त नहीं है। ऐसा सिस्टमहोना चाहिए जिसमें ट्रांजिकशन और बिक्री प्रक्रिया का रिकॉर्ड उपलब्ध हो और किसी शिकायत की स्थिति में उसकी जांच की जा सके।

लाईफ वर्सिटी- क्या आने वाले समय में तकनिकी ओवर चार्जिंग को पूरी तरह रोक सकती है?

■ **MD:** देखिये कोई भी टेक्नोलोजी अपने आप में सम्पूर्ण समाधान नहीं होती। तकनीक मोनिटरिंग को मजबूत कर सकती है, ट्रांजिकशन ट्रेल दे सकती है और हो रही अनियमितताओं की पहचान करने में मदद कर सकती है। लेकिन इसके साथ फील्ड लेवल मोनिटरिंग और जवाबदेही भी जरूरी है। हमारा प्रयास है कि टेक्नोलॉजी को केवल रिकॉर्ड-कीपिंग तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे गवर्नेंस टूल बनाया जाए।

लाईफ वर्सिटी-CSMCL की दुकानों में बारकोड स्कैनर्स और ब्लूटूथ प्रिंटर्स जैसी व्यवस्थाओं आम उपभोक्ता को इससे क्या फर्क पड़ेगा?

■ **MD:** इसका सबसे बड़ा फायदा ट्रांजैक्शन को अधिक व्यवस्थित और ट्रेसेबल बनाना है। हम चाहते हैं कि रिटेल प्वाइंट पर बिलिंग और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की प्रक्रिया अधिक स्टैंडर्डाइज्ड हो। टेक्नोलॉजी का फायदा तभी है जब उसका असर अंतत: कस्टमर एक्सपीरियंस पर दिखाई दे।

लाईफ वर्सिटी- कैश चेस्ट और लॉकर जैसी व्यवस्थाओं की जरूरत क्यों पड़ी?

■ **MD:** कैश मैनेजमेंट किसी भी बड़े रिटेल नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम चाहते हैं कि कैश हैंडलिंग में सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों मजबूत हों। कैश चेस्ट और लॉकर जैसी व्यवस्थाएं इसी दिशा में हैं।

लाईफ वर्सिटी- CSMCL को लेकर अतीत में कई तरह के विवाद और सवाल भी सामने आए हैं। क्या आपको लगता है कि नई तकनिकी इन पुराने मामलों का समाधान कर सकती है?

■ **MD:** टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से गवर्नेंस को मजबूत करने में मदद कर सकती है, लेकिन इसे अकेला समाधान नहीं कहा जा सकता। गवर्नेंस में क्लियर प्रोसेस, अप्रूवल्स, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट, मोनिटरिंग और जिम्मेदारी—सभी जरूरी हैं। टेक्नोलॉजी इसमें प्रारंभिक चेतावनी सिस्टम की तरह काम कर सकती है।

लाईफ वर्सिटी- एक बड़ा सवाल यह भी है कि शराब की बिक्री से सरकार को रेवेन्यूमिलता है, लेकिन इसके सामाजिक प्रभाव भी हैं?

■ **MD:** यह एक संवेदनशील विषय है। हम मानते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी के साथसोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावनाभी होनी चाहिए। CSMCL का दायित्व रेगुलेटेड रिटेल व्यवस्था को संचालित करना है। लेकिन हम इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं हैं कि शराब का सामाजिक प्रभाव होता है। इसलिए कानून और नियमन के पालन के साथ अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन जैसे विषय भी महत्वपूर्ण हैं। जहां जरूरत हो, वहां हेल्थ और डी-एडिक्ट्शन से जुड़े संस्थानों तथा संबंधित विभागों के साथ को-ओर्डिनेशन भी जरूरी है।

लाईफ वर्सिटी- कई जगह शराब दुकानों के आसपास या मुख्य सड़कों पर ग्राहकों की भीड़ के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। कई बार इसका असर आसपास के दुकानदारों और राहगीरों पर भी पड़ता है।

■ **MD:** यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण विषय है। शराब की दुकान केवल एक रिटेल प्वाइंट नहीं है, वह जिस लोकेशन पर है, वहां के ट्रैफिक और आसपास के लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर किसी दुकान के कारण सड़क पर भीड़ बढ़ रही है या ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है, तो हमें इसे केवल ट्रैफिक पुलिस का विषय मानकर नहीं चलना चाहिए। संबंधित विभागों के साथ मिलकर इसका समाधान तलाशना जरूरी है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि दुकान की लोकेशन, प्रवेश और निकास की व्यवस्था, पार्किंग की स्थिति और ग्राहकों की भीड़—इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए।

इस बातचीत से इतना स्पष्ट है कि CSMCL अब सिर्फ शराब की बिक्री तक सीमित व्यवस्था नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, डेटा और बेहतर गवर्नेंस की ओर बढ़ता एक बड़ा सिस्टम है।

लेकिन असली बदलाव तब माना जाएगा, जब इसका असर स्टॉक से लेकर काउंटर तक और काउंटर से लेकर सड़क तक दिखाई दे। सही कीमत, पारदर्शी व्यवस्था, कम जाम और जवाबदेही—यही तय करेंगे कि यह बदलाव सिर्फ सिस्टम में आया है या सचमुच आम आदमी की जिंदगी में भी। क्योंकि आम आदमी को कीमत चाहिए, सड़क पर जाम नहीं और शिकायत पर सिर्फ आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए। CSMCL कितना स्मार्ट हो रहा है, यह उसके सिस्टम बताएंगे; लेकिन वह कितना जिम्मेदार है, इसका जवाब सड़क, दुकान और ग्राहक देगा।

कैशलेस हुई 49 प्रीमियम शराब दुकान

छत्तीसगढ़ में प्रीमियम शराब दुकानों पर भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। आबकारी विभाग के आदेश के मुताबिक 1 अक्टूबर 2026 से प्रदेश की 49 प्रीमियम शराब दुकानों को कैशलेस कर दिया गया है। यानी ग्राहकों से नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत शराब खरीदने के बाद ग्राहक को दुकान पर उपलब्ध QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन भुगतान करना होगा। विभाग के अनुसार इससे हर बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा और लेनदेन की निगरानी आसान होगी। इस बदलाव का सीधा असर प्रीमियम शराब दुकानों से खरीदारी करने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा. जिन ग्राहकों को अब तक नगद भुगतान करने की आदत रही है, उन्हें 1 अक्टूबर से डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करना होगा।

बीरगांव बदल रहा है, क्या शहर भी बेहतर हो रहा है?



बीरगांव की विकास यात्रा इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमती है। एक ओर औद्योगिक गतिविधियां और नई संभावनाएं हैं, तो दूसरी ओर सड़क, पेयजल, नाली, सीवरेज, स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियां हैं। रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू की भूमिका भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है। क्षेत्र की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, विकास कार्यों के लिए प्रयास करना और योजनाओं को जमीन पर उतारने में सहयोग करना जनप्रतिनिधित्व की अहम जिम्मेदारियां हैं।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटा बीरगांव कभी गांवों, खेतों और ग्रामीण जीवन के लिए जाना जाता था। समय के साथ यहां औद्योगिक गतिविधियां बढ़ीं, रोजगार के अवसर विकसित हुए और आबादी का विस्तार होने लगा। आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों ने इस इलाके की आर्थिक पहचान को मजबूत किया, लेकिन तेजी से बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य ने नागरिक सुविधाओं पर दबाव भी बढ़ाया। आज बीरगांव केवल एक विस्तारित बस्ती नहीं, बल्कि एक ऐसे शहरी क्षेत्र के रूप में सामने है, जिसे अपनी बढ़ती आबादी की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक सुविधाओं और सुनियोजित विकास की आवश्यकता है।

रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू की भूमिका भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने 9 मार्च 2026 को विधानसभा में क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्या उठाए जाने का उल्लेख सामने आया। इस संदर्भ में मुख्य मुद्दा यह था कि नगर निगम में शामिल होने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में शहरी व्यवस्था के अनुरूप सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। यह सवाल बीरगांव के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शहर का विस्तार तभी सार्थक होगा, जब पुरानी बस्तियों और नई आबादी को समान रूप से विकास की योजना में शामिल किया जाए।

40 वार्डों तक विकास पहुंचाने की पहल

बीरगांव नगर निगम के सभी 40 वार्डों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अक्टूबर 2025 में नगर उत्थान योजना के तहत लगभग 27 करोड़ रुपये तथा अधोसंरचना मद से करीब 6 करोड़ रुपये की स्वीकृति की जानकारी सामने आई थी। इन योजनाओं में सीसी रोड, कांक्रीटीकरण, नाली निर्माण, पेवर और उद्यानों के रखरखाव जैसे कार्य शामिल हैं।

इन कार्यों का उद्देश्य शहर की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। बेहतर सड़कें आवागमन आसान बनाती हैं, नालियां जल निकासी में मदद करती हैं और



- रावांभाटा बंजारी नगर, शक्तिपारा, मठपारा एवं शीतलापारा उरकुला एवं मजदूर नगर सरोरा में सर्वेक्षण करवाकर नियमानुसार आवासीय पट्टा वितरण।
- निकाय क्षेत्र में एसटीपी निर्माण- 82 करोड
- बीरगांव में ओवर हैड टंकी एवं पाईप लाईन विस्तारीकरण कार्य- 10 करोड़
- अधोसंरचना मद में सड़क, नाली निर्माण हेतु- 5 करोड
- सरोरा में खेल मैदान विकास- 5 करोड़
- बीरगांव में नालंदा परिसर निर्माण- 5 करोड़

विकसित सार्वजनिक स्थल नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। विकास का लाभ प्रमुख मार्गों के साथ सभी वार्डों और मोहल्लों तक पहुंचना जरूरी है।

135 करोड़ से अधिक के कार्य, 110 करोड़ की नई सौगात

23 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बीरगांव प्रवास के दौरान 135 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया। साथ ही करीब 110 करोड़ रुपये के नए विकास कार्यों की घोषणा हुई।

सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार, पिछले ढाई वर्षों में बीरगांव नगर निगम क्षेत्र के लिए 160 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य मिले हैं, जिनमें करीब 90 करोड़ रुपये के कार्य पूरे हो चुके हैं।

ये आंकड़े बीरगांव में विकास गतिविधियों के बढ़ते दायरे को दर्शाते हैं। हालांकि, लोकार्पित, भूमिपूजन किए गए और घोषित कार्य विकास के अलग-अलग चरण हैं। इनका वास्तविक प्रभाव समयबद्ध क्रियान्वयन और नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं से तय होगा।

82 करोड़ का सीवेज प्लांट, पेयजल व्यवस्था को मजबूती

बीरगांव के लिए 82 करोड़ रुपये का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है। तेजी से बढ़ती आबादी वाले शहर में गंदे पानी का वैज्ञानिक उपचार स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के प्रभावी संचालन से सीवरेज प्रबंधन को व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है।

वहीं, लगभग 10 करोड़ रुपये की पेयजल व्यवस्था से संबंधित ओवरहेड टैंक और पाइपलाइन विस्तार की योजना जल वितरण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। नियमित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना शहरी विकास की बुनियादी जरूरत है।

शिक्षा और खेल में युवाओं को अवसर

बीरगांव में युवाओं के लिए शैक्षणिक और खेल सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है। नालंदा परिसर के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये और शासकीय महाविद्यालय में ई-लाइब्रेरी के लिए 89 लाख रुपये का उल्लेख सामने आया है।

ये सुविधाएं विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री, डिजिटल संसाधनों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने में मदद कर सकती हैं। इससे उन युवाओं को विशेष लाभ मिल सकता है, जिन्हें पढ़ाई के लिए निजी पुस्तकालयों या दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है।

सरोरा में खेल मैदान के विकास की पहल भी स्थानीय खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। पर्याप्त सुविधाएं, प्रशिक्षण और रखरखाव की व्यवस्था विकसित होने से युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।

आवास और सुरक्षा पर भी ध्यान

बीरगांव में लगभग 42 करोड़ रुपये की आवास संबंधी घोषणा का उल्लेख सामने आया है। इसका लाभ पात्र परिवारों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचना महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा नगर निगम को दो नए अग्निशमन वाहन दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

औद्योगिक गतिविधियों और घनी आबादी वाले क्षेत्र में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार आपातकालीन सुरक्षा की दृष्टि से अहम है। वाहनों के साथ प्रशिक्षित कर्मियों, पर्याप्त उपकरणों और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था की उपलब्धता भी जरूरी है।

विधायक मोतीलाल साहू की भूमिका

रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू की भूमिका क्षेत्र की समस्याओं को शासन तक पहुंचाने, विकास प्रस्तावों को आगे बढ़ाने और संबंधित विभागों के साथ समन्वय के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। बीरगांव के सामने अब औद्योगिक विकास को बेहतर शहरी जीवन में बदलने की चुनौती है। सड़क, पेयजल, सीवरेज, शिक्षा, खेल, आवास और सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार कर सकती हैं।विकास की असली पहचान घोषणाओं से नहीं, नागरिकों के जीवन में आने वाले बदलाव से बनती है। यदि योजनाएं समय पर पूरी होती हैं और उनका लाभ सभी वार्डों तक पहुंचता है, तो बीरगांव औद्योगिक पहचान के साथ एक व्यवस्थित, स्वच्छ और आधुनिक शहर के रूप में भी अपनी जगह मजबूत कर सकता है।

आने वाले वर्षों में बीरगांव की पहचान केवल उद्योगों और बढ़ती आबादी से नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित, स्वच्छ और नागरिकों के अनुकूल शहर के रूप में भी बननी चाहिए। यही विकास की असली कसौटी होगी—और यही बीरगांव के भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद भी है।



विजयादशमी

की हार्दिक शुभकामनाएं

SCG MultiMedia

MSME Reg. : UDYAM-CG-14-0068779

सेवा के 25 वर्ष
सुशासन | गरीब कल्याण | राष्ट्र निर्माण

सेवा सेतु

जनता के द्वार, डिजिटल सरकार

दफ्तरों के चक्कर खत्म



अधिक जानकारी हेतु
▸ स्कैन करें
या विजिट करें

sewasetu.cgstate.gov.in

92034 06400





संवाद- 14106/104